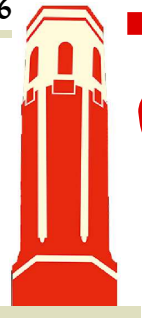


- देहरादून
- वर्ष 34
- अंक 276
- पृष्ठ 8
- मूल्य ₹ 1.00



दून वैली मेल

सांध्य दैनिक

आर.एन.आई. : 59626/94

email: doonvalley_news@yahoo.com

Website: dunvalleymail.com

डीएवीपी से मान्यता प्राप्त

11 घंटे भी नहीं चला विधानसभा सत्र

◆ करोड़ों खर्च होने के बाद भी प्रश्नकाल में नहीं हो सका एक भी सवाल

कार्यालय संवाददाता
गैरसैंण। ग्रीष्मकालीन राजधानी भराड़ीसैंण में उत्तराखंड विधानसभा का सत्र सियासी हंगामे, आरोप-प्रत्यारोप और विपक्ष के विरोध के बीच अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गया। बुधवार को सत्र के दूसरे दिन कांग्रेस विधायकों ने काले झंडे लहराकर, कागज फेंककर और वेल में पहुंचकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। इसके बावजूद सदन में 7844.18 करोड़ रुपये का अनुपूरक बजट और कुल 10 विधेयक पारित कर दिए गए। विपक्ष ने सत्र की अवधि बेहद कम रखने और जनहित के मुद्दों पर पर्याप्त चर्चा नहीं कराने का आरोप लगाया। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी ने दोपहर बाद सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करने की घोषणा कर दी। इस तरह गैरसैंण में विधानसभा की कार्यवाही 11 घंटे भी नहीं चल सकी।

सत्र के दूसरे दिन सदन की कार्यवाही शुरू होते ही सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच टकराव की स्थिति बन गई। कांग्रेस विधायक काले झंडे लेकर वेल में पहुंच गए और कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या से जुड़े कथित भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच की मांग करने लगे। विपक्ष ने नियम 310 के तहत इस मुद्दे पर चर्चा कराने की मांग उठाई। कांग्रेस विधायकों का आरोप था कि इतने गंभीर मामले पर सदन में जवाबदेही तय होनी चाहिए, जबकि सत्ता पक्ष ने विपक्ष के रवैये पर सवाल उठाए।

हंगामे के कारण प्रश्नकाल में एक भी प्रश्न नहीं

◆ आखिर कहाँ गिरा 210 करोड़ का झुमका



हो सका। शून्यकाल में भी सीमित चर्चा हो पाई और विधायक मोहम्मद शहजाद ही अपना प्रश्न रख सके।

इस दौरान कांग्रेस विधायकों के 210 का झुमका कहाँ गिराश नारे ने सदन में राजनीतिक माहौल को और गरमा दिया। यह नारा मंत्री रेखा आर्या से जुड़े कथित 210 करोड़ रुपये के भ्रष्टाचार के आरोपों पर विपक्ष के विरोध का हिस्सा था। आरोपों की सत्यता पर कोई निष्कर्ष निकले बिना ही सदन में इस मुद्दे पर तीखी राजनीतिक बहस देखने को मिली।

कांग्रेस नेता प्रीतम सिंह ने मंत्री रेखा आर्या से जुड़े कथित भ्रष्टाचार के आरोपों की निष्पक्ष जांच की मांग

उठाई। कांग्रेस का कहना था कि मामले में उठे सवालों का जवाब मिलना चाहिए और सरकार को जांच के माध्यम से स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। वहीं, रेखा आर्या ने पलटवार करते हुए कांग्रेस के वर्ष 2012 से 2017 के शासनकाल का उल्लेख किया। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या ने सदन में महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की आवश्यकता पर जोर दिया, जबकि मुख्यमंत्री पुष्कर

सिंह धामी ने विपक्ष की ओर से काम रोको प्रस्ताव लाने की मंशा पर सवाल उठाए। दोनों पक्षों के बीच आरोप-प्रत्यारोप से सदन का माहौल लगातार गर्म बना रहा।

दोपहर 12 बजे कार्यवाही दोबारा शुरू होने पर भी विपक्ष का विरोध नहीं थमा। कांग्रेस विधायक काले झंडे लेकर फिर वेल में पहुंच गए और मंत्री से जुड़े आरोपों पर जवाब मांगने लगे। सत्ता पक्ष के विधायकों ने भी चकराता में एक परिवार को कांग्रेस नेताओं की ओर से कथित धमकी दिए जाने का मामला उठाया और जांच कर कार्रवाई की मांग की। इस तरह सदन में जनहित के मुद्दों पर चर्चा के बजाय राजनीतिक टकराव हावी रहा। विपक्ष के लगातार विरोध के बीच सरकार ने 7844.18 करोड़ रुपये का अनुपूरक बजट पारित करा लिया। इसके साथ ही सदन में कुल 10 विधेयक भी पारित हुए। कांग्रेस ने सत्र की अवधि और सदन में चर्चा के लिए मिले समय पर सवाल उठाए। विपक्ष का आरोप था कि इतने कम समय में प्रदेश के महत्वपूर्ण मुद्दों पर गंभीर और व्यापक चर्चा संभव नहीं है।

सत्र के अनिश्चितकाल के लिए स्थगित होने के बाद यह सवाल भी अहम हो गया कि क्या सदन की कार्यवाही में जनहित के मुद्दों को पर्याप्त जगह मिल पाई। बजट और विधेयकों का पारित होना सरकार के लिए विधायी उपलब्धि रहा, लेकिन प्रश्नकाल का

►► शेष पृष्ठ 2 पर

सियासी शोर में दबे 'पहाड़' के सवाल

कार्यालय संवाददाता
गैरसैंण। उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी भराड़ीसैंण में विधानसभा का सत्र शुरू हो चुका है। सदन में अनुपूरक बजट, विधायी कार्यवाही और सत्ता-विपक्ष के बीच सियासी टकराव है। सदन के बाहर भी प्रदर्शन और विरोध की राजनीति गरमा रही है। लेकिन इस राजनीतिक शोर के बीच पहाड़ की जनता के सवाल अपनी जगह खड़े हैं। बेरोजगारी से जूझते युवा रोजगार मांग रहे हैं, गांव पलायन की मार झेल रहे हैं, मरीज बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं के इंतजार में हैं और दूरस्थ क्षेत्रों के लोग सड़क, पेयजल तथा संचार जैसी बुनियादी सुविधाओं की उम्मीद लगाए बैठे हैं। ऐसे में विधानसभा के इस सत्र की सबसे बड़ी कसौटी यही है कि भराड़ीसैंण में कितनी राजनीतिक गर्मी पैदा हुई, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि यहां से जनता के जीवन में बदलाव लाने वाले कितने फैसले निकले।

राज्य गठन के बाद उत्तराखंड ने विकास के कई पड़ाव पार किए हैं, लेकिन

पहाड़ की मूल समस्याओं का पूरी तरह समाधान अब भी चुनौती बना हुआ है। जिस अलग राज्य की कल्पना रोजगार, बेहतर सुविधाओं और क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने के संकल्प के साथ की गई थी, उसकी कसौटी आज भी गांवों की स्थिति और युवाओं के भविष्य से तय होती है। भराड़ीसैंण में बैठने वाली सरकार से अपेक्षा भी यही है कि वह पर्वतीय क्षेत्रों की जरूरतों को प्राथमिकता दे। ऐसे में सत्र केवल विधेयकों को पारित करने और बजट की औपचारिकताएं पूरी करने तक सीमित नहीं रह सकता। सरकार ने लगभग 7412 करोड़ रुपये के अनुपूरक बजट को मंजूरी दी है। अब सवाल यह है कि अतिरिक्त धनराशि से प्रदेश की किन जरूरतों को पूरा किया जाएगा और इसका लाभ आम जनता तक कैसे पहुंचेगा। बजट का आकार सरकार की वित्तीय प्राथमिकताओं का संकेत देता है, लेकिन विकास की वास्तविक तस्वीर आवंटित धन के इस्तेमाल और उससे मिलने वाले परिणामों से बनती है।

प्रदेश में सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल और रोजगार जैसे क्षेत्रों में जरूरतें व्यापक हैं। दूरस्थ पर्वतीय इलाकों में स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी, विशेषज्ञ चिकित्सकों की उपलब्धता, विद्यालयों में शिक्षकों की

◆ रोजगार-पलायन तक सरकार के सामने सवालों की कतार
◆ सियासी तपिश के बीच बुनियादी सवालों पर लोगों की आस
◆ राजनीतिक शोर के बीच जनता की मूलभूत समस्याएं खड़ी

तैनाती और गांवों तक नियमित परिवहन जैसी समस्याएं लोगों के दैनिक जीवन को प्रभावित करती हैं। ऐसे में जनता यह जानना चाहेगी कि अनुपूरक बजट से इन क्षेत्रों में कितनी राहत मिलेगी, कौन-सी योजनाएं प्राथमिकता पर पूरी होंगी और उनके क्रियान्वयन की समयसीमा क्या होगी। सरकार के सामने यह साबित करने की चुनौती है कि बजट केवल सरकारी खातों में दर्ज अतिरिक्त प्रावधान नहीं, बल्कि

विकास कार्यों को गति देने का माध्यम बनेगा। योजनाओं के लिए धन उपलब्ध कराने के साथ यह सुनिश्चित करना भी जरूरी है कि उसका समय पर और प्रभावी उपयोग हो।

उत्तराखंड में बेरोजगारी ऐसा मुद्दा है, जिसे चुनावी बहस से अलग नहीं रखा जा सकता। सरकारी नौकरियों की तैयारी कर रहे युवाओं की अपेक्षाएं, भर्ती प्रक्रियाओं की पारदर्शिता और निजी क्षेत्र में सीमित अवसर रोजगार के सवाल को लगातार प्रासंगिक बनाए हुए हैं। चुनाव से पहले सरकार अपनी उपलब्धियां गिनाएगी और विपक्ष कमियों को सामने रखेगा, लेकिन युवाओं के लिए असली सवाल अवसरों का है। कितने युवाओं को स्थायी रोजगार मिला, कौशल प्रशिक्षण के बाद कितनों को काम मिला और स्वरोजगार की योजनाओं से कितने उद्यम स्थापित हुए इन सवालों के जवाब जरूरी हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में पर्यटन, बागवानी, कृषि आधारित उद्योग, खाद्य प्रसंस्करण और डिजिटल सेवाओं के

जरिए स्थानीय रोजगार बढ़ाने की संभावनाएं हैं। इसके लिए प्रशिक्षण के साथ बाजार, पूंजी और बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता भी सुनिश्चित करनी होगी।

युवाओं को केवल सरकारी नौकरी की प्रतीक्षा में रहने के लिए छोड़ देना समाधान नहीं है। सरकार को ऐसे अवसर विकसित करने होंगे, जिनसे युवा अपने ही क्षेत्र में सम्मानजनक आजीविका हासिल कर सकें। पलायन उत्तराखंड के विकास मॉडल के सामने सबसे गंभीर सवालों में से एक है। गांवों से लोगों का बाहर जाना केवल रोजगार की कमी का परिणाम नहीं, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन और बाजार जैसी सुविधाओं की अनुपलब्धता से भी जुड़ा है। जब गांव में बच्चों की पढ़ाई और परिवार के उपचार की पर्याप्त व्यवस्था नहीं होती, तब बेहतर भविष्य की तलाश में शहरों की ओर जाना मजबूरी बन जाता है।

ऐसे में पलायन रोकने की नीति को केवल घोषणाओं तक सीमित नहीं रखा

►► शेष पृष्ठ 2 पर

दून वैली मेल

संपादकीय

चुनावी साल में जेनजी पर नजर

उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव की आहट के बीच धामी सरकार की प्राथमिकताओं में युवा पीढ़ी का महत्व बढ़ना स्वाभाविक है। भराड़ीसैंण में पेश अनुपूरक बजट में जेनजी यानी नई पीढ़ी को केंद्र में रखने की झलक दिखाई देती है। यह केवल बजट के प्रावधानों का सवाल नहीं, बल्कि उस युवा वर्ग की आकांक्षाओं को समझने की चुनौती भी है, जो रोजगार, पारदर्शिता, बेहतर शिक्षा और भविष्य की सुरक्षा चाहता है। चुनावी वर्ष में युवाओं पर सरकार का यह फोकस राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, लेकिन इसकी वास्तविक सफलता घोषणाओं से नहीं, जमीन पर दिखाई देने वाले परिणामों से तय होगी। उत्तराखंड की राजनीति में युवा हमेशा से निर्णायक भूमिका में रहे हैं। अलग राज्य की मांग के पीछे भी बेहतर भविष्य, रोजगार और पहाड़ में सम्मानजनक जीवन की आकांक्षा थी। राज्य गठन के 26 वर्ष बाद भी यदि युवाओं को अवसरों की तलाश में दूसरे राज्यों का रुख करना पड़ता है तो यह विकास के दावों के सामने बड़ा प्रश्न है। ऐसे में नई पीढ़ी को साधने की किसी भी सरकारी पहल का मूल्यांकन इसी कसौटी पर होना चाहिए कि वह युवाओं के जीवन में कितना वास्तविक बदलाव ला रही है। आज का युवा केवल योजनाओं की सूची या सरकारी आश्वासनों से संतुष्ट होने वाला नहीं है। उसके सामने प्रतियोगी परीक्षाओं की अनिश्चितता, भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता, निजी क्षेत्र में सीमित अवसर, कौशल के अनुरूप काम और स्वरोजगार के लिए पूंजी जैसी व्यावहारिक चुनौतियां हैं। इंटरनेट और सामाजिक माध्यमों के विस्तार ने उसे सूचना के प्रति सजग बनाया है। वह सरकार के दावों की तुलना आंकड़ों और अनुभवों से करता है। यही कारण है कि जेनजी को केंद्र में रखने वाली नीतियों में संवाद, जवाबदेही और समयबद्ध क्रियान्वयन का महत्व किसी भी बजटीय घोषणा से कम नहीं है। उत्तराखंड जैसे पर्वतीय राज्य के लिए युवा नीति का अर्थ मैदानी क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ाने तक सीमित नहीं हो सकता। पहाड़ के गांवों में शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, संचार और बाजार की सुविधाओं को मजबूत किए बिना पलायन की समस्या का स्थायी समाधान संभव नहीं है। स्थानीय संसाधनों पर आधारित उद्योग, पर्यटन, कृषि, बागवानी, जड़ी-बूटी, हस्तशिल्प और डिजिटल सेवाओं में रोजगार के नए अवसर पैदा करने होंगे। युवाओं को केवल नौकरी खोजने वाला नहीं, बल्कि अपने क्षेत्र में रोजगार सृजित करने में सक्षम बनाना होगा। यह भी ध्यान रखना होगा कि जेनजी कोई एकरूप समूह नहीं है। शहरों में पढ़ने वाले युवाओं की जरूरतें पहाड़ के दूरस्थ गांवों में रहने वाले युवाओं से अलग हैं। तकनीकी शिक्षा प्राप्त युवाओं की अपेक्षाएं और पारंपरिक आजीविका से जुड़े परिवारों के युवाओं की चुनौतियां भी समान नहीं हैं। इसलिए सरकार की प्राथमिकता ऐसी योजनाएं होनी चाहिए, जिनका लाभ सामाजिक और भौगोलिक असमानताओं के कारण पीछे छूट रहे युवाओं तक भी पहुंचे। बजट में धन का प्रावधान तभी सार्थक होगा, जब उसके उपयोग, लाभार्थियों और परिणामों का स्पष्ट हिसाब सामने आए। चुनावी वर्ष में युवाओं पर बढ़ता ध्यान सत्ता पक्ष की राजनीतिक रणनीति का हिस्सा भी हो सकता है। लोकतंत्र में चुनाव से पहले सरकारों का अपनी प्राथमिकताओं की समीक्षा करना अस्वाभाविक नहीं है। समस्या तब पैदा होती है, जब नीतियां दीर्घकालिक जरूरतों के बजाय तात्कालिक राजनीतिक लाभ से संचालित होने लगती हैं। युवा वर्ग को यदि केवल चुनावी समर्थन जुटाने का माध्यम समझा गया तो यह अवसर हाथ से निकल सकता है। इसके विपरीत, यदि सरकार युवाओं की समस्याओं को शासन की स्थायी प्राथमिकता बनाती है तो उसका लाभ चुनावी गणित से कहीं आगे तक जाएगा। अनुपूरक बजट में जेनजी पर फोकस की झलक को इसी संदर्भ में देखना चाहिए। बजट का आकार या घोषणाओं की संख्या अपने आप में उपलब्धि नहीं होती। महत्वपूर्ण यह है कि आवंटित धन का कितना हिस्सा निर्धारित समय में खर्च होता है, कितने युवाओं को प्रशिक्षण के बाद वास्तविक रोजगार मिलता है, कितने नए उद्यम खड़े होते हैं और पहाड़ के कितने गांवों में आजीविका के अवसर बढ़ते हैं। इन सवालों के जवाब ही सरकारी मंशा और उसके परिणामों के बीच की दूरी को स्पष्ट करेंगे। धामी सरकार के सामने अवसर भी है और चुनौती भी। युवा आबादी को राज्य की सबसे बड़ी ताकत में बदलने के लिए उसे रोजगार, शिक्षा, कौशल और उद्यमिता को एक-दूसरे से जोड़ना होगा। भर्ती प्रक्रिया में भरोसा बहाल करना, सरकारी योजनाओं की जानकारी सरलता से उपलब्ध कराना और युवाओं की शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई करना भी उतना ही जरूरी है। सरकार को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि बजट का लाभ केवल बड़े शहरों और पहले से सक्षम वर्ग तक सीमित न रह जाए। आखिरकार, उत्तराखंड का युवा भविष्य की संभावना है, केवल चुनावी आंकड़ा नहीं। अनुपूरक बजट में उसकी चिंता दिखाई देना सकारात्मक संकेत हो सकता है, लेकिन असली परीक्षा अब क्रियान्वयन की है। सरकार यदि इस अवसर को ठोस रोजगार, पारदर्शी व्यवस्था और स्थानीय विकास में बदल पाती है तो जेनजी का भरोसा जीतने की दिशा में आगे बढ़ेगी। अन्यथा चुनावी साल में दिखाई दिया यह फोकस बजट के पन्नों तक ही सिमटकर रह जाएगा।

11 घंटे भी नहीं चला विधानसभा सत्र..

बाधित होना और विपक्ष का लगातार हंगामा विधानसभा की कार्यवाही पर सवाल छोड़ गया। विधानसभा सत्र के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गैरसैंण में 231.91 करोड़ रुपये की 12 विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इनमें 197.87 करोड़ रुपये की छह योजनाओं का शिलान्यास तथा 34.०4 करोड़ रुपये की छह योजनाओं का लोकार्पण शामिल है। इन योजनाओं में पेयजल, सड़क, शिक्षा, सुरक्षा और पुलिस अवस्थापना से जुड़ी परियोजनाएं शामिल हैं। सरकार ने विकास योजनाओं के माध्यम से क्षेत्र में बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करने का संदेश दिया, लेकिन विधानसभा का छोटा सत्र और हंगामे के कारण बाधित कार्यवाही राजनीतिक बहस का प्रमुख विषय बनी रही।

टिकट की जंग में ‘नई पीढ़ी’

कार्यालय संवाददाता
देहरादून। उत्तराखंड में 2०27 के विधानसभा चुनाव की असली लड़ाई अभी जनता के बीच नहीं, राजनीतिक दलों के भीतर आकार ले रही है। टिकट की दावेदारी ने नेताओं की धड़कनें बढ़ा दी हैं। पुराने दिग्गज अपनी राजनीतिक जमीन बचाने में जुटे हैं तो नई पीढ़ी विधानसभा पहुंचने के लिए पूरा दम लगा रही है। वर्षों तक संगठन का झंडा उठाने वाले युवा नेता अब केवल चुनाव प्रचार में भीड़ जुटाने और

वरिष्ठ नेताओं के स्वागत तक सीमित रहने को तैयार नहीं हैं। उनकी नजर सीधे विधानसभा की कुर्सी पर है। यही महत्वाकांक्षा भाजपा और कांग्रेस के लिए नई चुनौती बन रही है। सवाल अब सिर्फ यह नहीं कि किसे टिकट मिलेगा, बल्कि यह भी है कि टिकट कटने के बाद कौन पार्टी में रहेगा और कौन अपने ही दल के चुनावी समीकरणों पर चोट करेगा।

चुनावी साल में हर दावेदार खुद को जिताऊ बता रहा है। कोई अपने जनसंपर्क को ताकत बता रहा है तो कोई संगठन में वर्षों की मेहनत को टिकट का आधार मान रहा है। कुछ चेहरे अपनी राजनीतिक विरासत के सहारे दावेदारी मजबूत कर रहे हैं तो कुछ युवा नेता बदलाव की जरूरत को अपना हथियार बना रहे हैं। लेकिन इन दावों के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या राजनीतिक दल वास्तव में नई पीढ़ी को अवसर देना चाहते हैं या युवाओं का इस्तेमाल केवल चुनावी भीड़ और प्रचार अभियान तक ही सीमित रहेगा? सत्ता में लगातार तीसरी बार वापसी का लक्ष्य लेकर चल रही भाजपा के लिए टिकट वितरण आसान नहीं होगा। मौजूदा विधायकों का प्रदर्शन, क्षेत्र में नाराजगी, संगठन की पसंद, नए चेहरों की दावेदारी और जीतने की संभावना के बीच संतुलन बनाना होगा। पार्टी के सामने एक तरफ सत्ता विरोधी रुझान की आशंका है, दूसरी तरफ उन नेताओं की महत्वाकांक्षा, जो लंबे समय से टिकट की प्रतीक्षा कर रहे हैं।

यदि पार्टी मौजूदा विधायकों पर फिर भरोसा करती है तो नए दावेदारों की नाराजगी बढ़ सकती है। यदि बड़े पैमाने पर चेहरे बदले जाते हैं तो पुराने नेताओं और उनके समर्थकों को साधना मुश्किल

अज्ञात वाहन की चपेट में आकर मोटरसाईकिल सवार की मौत

संवाददाता
देहरादून। अज्ञात वाहन की चपेट में आकर मोटरसाईकिल सवार की मौत हो गयी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार बालूवाला निवासी मंजू देवी ने विकासनगर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराते हुए बताया कि उसका पति रामकुमार अपनी मोटरसाईकिल से घर की तरफ आ रहा था। जब वह बरोटीवाला के पास पहुंचा तभी अज्ञात वाहन ने उसको अपनी चपेट में ले लिया जिससे वह गम्भीर रूप से घायल हो गये। आसपास के लोगों ने उनको अस्पताल में भर्ती कराया जहां उपचार के दौरान उनकी मृत्यु हो गयी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

होगा। टिकट कटने की स्थिति में बागी उम्मीदवार खड़े होने का जोखिम भी रहेगा। भाजपा की चुनौती इसलिए दोहरी है कि उसे जिताऊ प्रत्याशी भी चुनना है और टिकट न पाने वाले नेताओं को चुनाव के दौरान पार्टी के खिलाफ सक्रिय होने से भी रोकना है। यहां एक और सवाल महत्वपूर्ण है। क्या संगठन की मजबूती के नाम पर हर मौजूदा विधायक को दोबारा मौका मिलना चाहिए या जनता के बीच कमजोर पड़ चुके चेहरों की जगह नए लोगों को

◆2०27 में भाजपा-कांग्रेस के सामने दोहरी चुनौती◆पुराने दिग्गजों की कुर्सी पर नए दावेदारों की नजर◆टिकट कटा तो बिगड़ सकता है चुनावी गणित

आगे बढ़ाना चाहिए? इसका जवाब केवल संगठनात्मक आकलन से नहीं, क्षेत्रीय जनमत और उम्मीदवारों के वास्तविक प्रदर्शन से मिल सकता है।

कांग्रेस के सामने चुनौती और भी संवेदनशील है। पार्टी को सत्ता में वापसी के लिए भाजपा के खिलाफ असंतोष को अपने पक्ष में बदलना है, लेकिन टिकट वितरण के दौरान अपने ही नेताओं के बीच सहमति बनाना बड़ी परीक्षा होगी। कई सीटों पर पुराने नेताओं की दावेदारी के साथ युवा चेहरों की महत्वाकांक्षा टकरा सकती है। कांग्रेस के लिए सबसे बड़ा जोखिम यह होगा कि टिकट का फैसला चुनावी योग्यता के बजाय गुटीय समीकरणों के चश्मे से देखा जाए। यदि किसी दावेदार को लगता है कि उसकी अनदेखी हुई है तो वह बगावत कर सकता है, दूसरे दल का रुख कर सकता है या भीतर रहकर ही पार्टी की चुनावी सक्रियता को कमजोर कर सकता है। ऐसी स्थिति में नुकसान केवल एक सीट तक सीमित नहीं रहता, बल्कि आसपास की सीटों पर भी संगठन और प्रचार अभियान प्रभावित हो सकते हैं।

कांग्रेस के सामने असली कसौटी यह होगी कि वह युवा नेतृत्व को कितनी जगह देती है और अनुभवी नेताओं की राजनीतिक उपयोगिता का किस तरह आकलन करती है। केवल नए चेहरों को आगे करना समाधान नहीं, लेकिन योग्य युवाओं को लगातार पीछे रखना भी पार्टी के लिए भविष्य की चुनौती बन सकता है। उत्तराखंड की राजनीति में इस बार छोटे दलों और नए राजनीतिक मंचों की

सक्रियता भी टिकट की लड़ाई को प्रभावित कर सकती है। उत्तराखंड क्रांति दल का सभी 7० सीटों पर चुनाव लड़ने का एलान, आम आदमी पार्टी की सक्रियता और निर्दलीय विधायक उमेश कुमार की नई पार्टी बनाने की घोषणा ने संभावित दावेदारों के सामने वैकल्पिक रास्तों की चर्चा को बढ़ाया है।

भाजपा और कांग्रेस से टिकट न मिलने पर कुछ नेता इन मंचों की ओर रुख कर सकते हैं। ऐसे नेताओं के पास स्थानीय पहचान और व्यक्तिगत समर्थकों का आधार हो तो वह मुकाबले को प्रभावित कर सकते हैं। हालांकि, बड़े दल से निकलना

और नए दल के टिकट पर जीत हासिल करना अलग-अलग चुनौतियां हैं। किसी नेता का व्यक्तिगत प्रभाव हर राजनीतिक मंच पर समान रूप से काम करेगा, इसकी गारंटी नहीं है।

नई पीढ़ी की बढ़ती दावेदारी राजनीतिक दलों के सामने एक बुनियादी सवाल खड़ा करती है कि क्या युवाओं को नेतृत्व में वास्तविक हिस्सेदारी मिलेगी या उन्हें केवल चुनावी नारों में जगह दी जाएगी? युवा होना अपने आप में जीत की गारंटी नहीं है, लेकिन अनुभव के नाम पर नए चेहरों के लिए रास्ते बंद कर देना भी राजनीतिक जड़ता को बढ़ा सकता है। राजनीतिक दलों को उम्मीदवार चुनते समय उम्र से अधिक जनाधार, काम, संगठनात्मक क्षमता और जनता के बीच विश्वसनीयता को महत्व देना होगा। नई पीढ़ी के दावेदारों को भी यह साबित करना होगा कि उनकी महत्वाकांक्षा केवल विधानसभा पहुंचने तक सीमित नहीं है, बल्कि उनके पास क्षेत्र की समस्याओं का ठोस समाधान भी है। 2०27 के चुनाव में भाजपा और कांग्रेस को विपक्षी दलों से मुकाबला करने से पहले अपने भीतर के असंतोष से निपटना होगा। भाजपा के लिए सत्ता में वापसी की रणनीति को टिकट वितरण के साथ संतुलित करना चुनौती होगी, जबकि कांग्रेस के लिए गुटीय प्रतिस्पर्धा के बीच एकजुटता बनाए रखना जरूरी होगा। छोटे दलों के सामने असंतुष्ट नेताओं की ताकत को अपने पक्ष में बदलने का अवसर होगा, लेकिन इसके लिए उन्हें संगठन और जनाधार भी खड़ा करना पड़ेगा।

सियासी शोर में दबे ‘पहाड़’ के सवाल..

जा सकता। स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ाने, कृषि और बागवानी को बाजार से जोड़ने, छोटे उद्यमों को प्रोत्साहन देने तथा पर्यटन से स्थानीय परिवारों की आय बढ़ाने की जरूरत है। सरकार को यह भी स्पष्ट करना चाहिए कि अब तक घोषित योजनाओं से कितने गांवों में आजीविका के अवसर बढ़े और उनके परिणामों का आकलन किस आधार पर किया जा रहा है। भराड़ीसैंण के सत्र में इन सवालों पर गंभीर चर्चा और ठोस निर्णय पहाड़ की जनता के भरोसे को मजबूत कर सकते हैं।

सत्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच टकराव स्वाभाविक है। सरकार का दायित्व अपनी नीतियों और योजनाओं का हिसाब देना है, जबकि विपक्ष की जिम्मेदारी जनता से जुड़े मुद्दों पर जवाब मांगना है। लेकिन लोकतंत्र में दोनों की भूमिका केवल आरोप-प्रत्यारोप तक सीमित नहीं हो

सकती। यदि विपक्ष सदन में बेरोजगारी, पलायन, स्वास्थ्य और शिक्षा के सवाल उठाता है तो उसे तथ्यों के साथ सरकार को जवाबदेह बनाने की कोशिश करनी चाहिए। वहीं सरकार को भी राजनीतिक आलोचना का जवाब केवल उपलब्धियों की सूची से नहीं, बल्कि स्पष्ट आंकड़ों और योजनाओं की प्रगति से देना होगा। असहमति लोकतंत्र की ताकत है, लेकिन उसका परिणाम जनता की समस्याओं के समाधान के रूप में सामने आना चाहिए। 2०27 के विधानसभा चुनाव से पहले यह सत्र राजनीतिक दलों के लिए अपनी प्राथमिकताएं सामने रखने का अवसर भी है। सत्ता पक्ष के लिए विकास कार्यों का हिसाब देने और विपक्ष के लिए जनता की समस्याओं को राजनीतिक विमर्श के केंद्र में लाने की चुनौती है। लेकिन मतदाता अंततः यह देखेगा कि उसके जीवन में कितना बदलाव आया।

यूकेडी:संघर्ष, पहचान और वजूद की तलाश

कार्यालय संवाददाता
देहरादून। उत्तराखंड क्रांति दल की कहानी उत्तराखंड राज्य आंदोलन के संघर्ष, क्षेत्रीय अस्मिता की राजनीति, सत्ता की संभावनाओं और राजनीतिक विफलताओं की कहानी है। जिस दल ने अलग पहाड़ी राज्य की मांग को आंदोलन से जनभावना बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, वह राज्य बनने के बाद उसी जनभावना को स्थायी राजनीतिक ताकत में नहीं बदल पाया। कभी उत्तराखंड की राजनीति में क्षेत्रीय विकल्प बनने की क्षमता रखने वाला यूकेडी आज भाजपा और कांग्रेस के बीच सिमटी सत्ता की राजनीति में अपनी जगह तलाश रहा है। अब 2०27 के विधानसभा चुनाव की आहट के बीच सवाल यही है कि क्या यूकेडी अपनी खोई जमीन वापस हासिल कर पाएगा या राज्य आंदोलन की विरासत केवल उसकी राजनीतिक पहचान बनकर रह जाएगी?

25 जुलाई 1979 को स्थापित यूकेडी ने अलग उत्तराखंड राज्य की मांग को संगठित राजनीतिक आवाज देने में अहम भूमिका निभाई। पर्वतीय क्षेत्रों की भौगोलिक परिस्थितियों, रोजगार, पलायन, संसाधनों पर स्थानीय अधिकार और लखनऊ में बैठे सत्ता प्रतिष्ठान की कथित उपेक्षा जैसे सवाल दल की राजनीति के केंद्र में रहे। डा. देवीदत्त पंत, काशी सिंह ऐरी और अन्य आंदोलनकारी नेताओं की अगुआई में दल ने पहाड़ की समस्याओं को अलग राज्य की मांग से जोड़ा। बाद के वर्षों में इंद्रमणि बडोनी और दिवाकर भट्ट जैसे नेताओं ने भी आंदोलन को व्यापक जनाधार देने में भूमिका निभाई।

199० के दशक में अलग राज्य की मांग ने व्यापक जनांदोलन का रूप लिया। वर्ष 1994 के आंदोलन, पुलिस कार्रवाई और रामपुर तिराहा कांड ने उत्तराखंड की राजनीति को निर्णायक मोड़ दिया। इस संघर्ष में यूकेडी की भूमिका महत्वपूर्ण रही, लेकिन आंदोलन केवल किसी एक दल का नहीं था। विभिन्न सामाजिक संगठनों, छात्र-युवा समूहों, महिला संगठनों और राजनीतिक कार्यकर्ताओं की भागीदारी ने इसे व्यापक जनआंदोलन बनाया। अंततः नौ नवंबर 2००० को उत्तराखंड अलग राज्य बना। मगर जिस राज्य की स्थापना

के लिए संघर्ष किया गया, उसके गठन के बाद क्षेत्रीय राजनीति को मजबूत करने का अवसर यूकेडी के हाथ से निकलने लगा।

अलग राज्य बनने के बाद यूकेडी के सामने सबसे बड़ी चुनौती आंदोलनकारी संगठन से प्रभावशाली राजनीतिक दल बनने की थी। जनता को उम्मीद थी कि पहाड़ की समस्याओं, स्थानीय रोजगार, पलायन, गैरसैंण में राजधानी और संसाधनों पर स्थानीय अधिकार जैसे मुद्दों को लेकर खड़ा हुआ दल राज्य की नीतियों को दिशा देगा। लेकिन भाजपा और कांग्रेस की मजबूत चुनावी मशीनरी के सामने यूकेडी अपना स्वतंत्र जनाधार कायम नहीं रख पाया।

◆उत्तराखंड की अलग पहचान की लड़ाई को घर-घर पहुंचाया ◆खुद राजनीतिक जमीन तलाशने को मजबूर है प्रदेश में यूकेडी ◆2027 के चुनाव में अस्तित्व बचाने, विरासत लौटाने की चुनौती

वर्ष 2००2 के विधानसभा चुनाव में यूकेडी को चार सीटें मिलीं। 2००7 में दल के दो विधायक चुने गए और भाजपा को सरकार बनाने के लिए समर्थन दिया। वर्ष 2०12 में भी यूकेडी के विधायकों के समर्थन ने सरकार गठन के समीकरणों में भूमिका निभाई। लेकिन सत्ता के समीकरणों में भागीदारी क्षेत्रीय दल को मजबूत जनाधार में बदलने के लिए पर्याप्त साबित नहीं हुई। यहीं यूकेडी की राजनीति का विरोधाभास सामने आया। जिस दल की पहचान सत्ता प्रतिष्ठान से संघर्ष करने वाले संगठन की थी, वह धीरे-धीरे सरकार बनाने और बचाने के गणित में उलझता दिखाई दिया। सत्ता में हिस्सेदारी के बावजूद वह अपनी मूल मांगों को निर्णायक राजनीतिक एजेंडा नहीं बना पाया। नतीजा यह रहा कि राज्य आंदोलन की विरासत तो उसके पास रही, लेकिन उस विरासत का चुनावी लाभ दूसरी पार्टियां उठाती रहीं।

यूकेडी की कमजोरी का एक बड़ा कारण आंतरिक मतभेद और गुटबाजी भी रही। नेतृत्व को लेकर विवाद, अलग-अलग राजनीतिक रास्ते अपनाने और संगठन में टूट ने दल की विश्वसनीयता को प्रभावित किया।

राज्य की राजनीति में क्षेत्रीय विकल्प बनने के लिए जिस एकजुट नेतृत्व, मजबूत संगठन और स्पष्ट राजनीतिक दिशा की जरूरत थी, यूकेडी वहां बार-बार पिछड़ता रहा। राजनीतिक विश्लेषणों में भी गुटबाजी और भाजपा-कांग्रेस के साथ बदलते समीकरणों को दल के पतन के प्रमुख कारणों में गिना गया है। इसके साथ ही भाजपा और कांग्रेस ने राज्य आंदोलन से जुड़े मुद्दों को अपने राजनीतिक विमर्श में जगह दी। गैरसैंण, पलायन, स्थानीय रोजगार और पर्वतीय विकास जैसे सवालों पर दोनों राष्ट्रीय दलों ने अपने-अपने तरीके से राजनीतिक दावे किए। इससे यूकेडी के लिए अपनी विशिष्ट पहचान को चुनावी

समर्थन में बदलना और कठिन होता गया।

2०27 का विधानसभा चुनाव यूकेडी के लिए सामान्य चुनाव से कहीं अधिक महत्वपूर्ण होगा। राज्य गठन के बाद एक चौथाई सदी से ज्यादा समय गुजर चुका है। नई पीढ़ी के मतदाताओं के लिए राज्य आंदोलन इतिहास का हिस्सा है, जबकि उनकी प्राथमिकताएं रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, पलायन, स्थानीय अर्थव्यवस्था और बेहतर बुनियादी सुविधाओं से जुड़ी हैं। यूकेडी को यह साबित करना होगा कि उसकी क्षेत्रीय राजनीति केवल अतीत के संघर्ष की याद नहीं, बल्कि वर्तमान समस्याओं का व्यावहारिक समाधान भी दे सकती है। दल के सामने तीन बड़ी चुनौतियां हैं। पहली, संगठन को गांवों और नगरों तक सक्रिय करना। दूसरी, युवा मतदाताओं के बीच विश्वसनीय राजनीतिक विकल्प के रूप में अपनी पहचान बनाना। तीसरी, भाजपा और कांग्रेस से अलग स्पष्ट आर्थिक, सामाजिक और विकास संबंधी एजेंडा पेश करना। केवल क्षेत्रीय अस्मिता का नारा पर्याप्त नहीं होगा। उसे रोजगार, पलायन रोकने, कृषि-बागवानी, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य और स्थानीय

संसाधनों पर अधिकार के सवालों पर ठोस कार्यक्रम देना होगा।

गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाने का सवाल भी यूकेडी की राजनीतिक पहचान से जुड़ा है। लेकिन इस मुद्दे को केवल प्रतीकात्मक बहस तक सीमित रखने के बजाय पर्वतीय क्षेत्रों में प्रशासनिक पहुंच, रोजगार और विकास के विकेंद्रीकरण से जोड़ना होगा। पहाड़ के गांव खाली हो रहे हों, युवा रोजगार के लिए बाहर जाने को मजबूर हों और स्वास्थ्य-शिक्षा की सुविधाओं के लिए लोगों को लंबी दूरी तय करनी पड़े, तो क्षेत्रीय दल की प्रासंगिकता उसके समाधान से ही तय होगी। यूकेडी के सामने सबसे बड़ा राजनीतिक प्रश्न यही है कि जिस राज्य की मांग को उसने दशकों तक उठाया, उसी राज्य में वह मजबूत चुनावी शक्ति क्यों नहीं बन पाया। इसका उत्तर केवल भाजपा-कांग्रेस के प्रभाव में तलाशना पर्याप्त नहीं होगा। संगठनात्मक कमजोरी, नेतृत्व के मतभेद, बदलते राजनीतिक समीकरण और आंदोलन के बाद स्पष्ट वैकल्पिक शासन मॉडल पेश करने में असफलता का भी ईमानदार मूल्यांकन करना होगा।

उत्तराखंड की राजनीति में क्षेत्रीय मुद्दे आज भी प्रासंगिक हैं। पलायन, स्थानीय रोजगार, जमीन और संसाधनों पर अधिकार तथा पर्वतीय क्षेत्रों में विकास का असंतुलन ऐसे सवाल हैं जिनका समाधान अब भी जनता की प्रमुख अपेक्षाओं में शामिल है। इसलिए यूकेडी के लिए संभावनाएं पूरी तरह समाप्त नहीं हुई हैं। लेकिन संभावनाओं को राजनीतिक ताकत में बदलने के लिए अतीत की उपलब्धियों का स्मरण करने से आगे बढ़ना होगा। राज्य आंदोलन ने यूकेडी को ऐतिहासिक पहचान दी, लेकिन उस पहचान को जनादेश में बदलना अब भी उसकी सबसे बड़ी परीक्षा है। 2०27 में दल के सामने केवल सीटें जीतने का लक्ष्य नहीं, बल्कि यह साबित करने की चुनौती भी होगी कि उत्तराखंड की क्षेत्रीय राजनीति के लिए उसके पास आज भी एक विश्वसनीय और प्रासंगिक विकल्प मौजूद है। वरना जिस आंदोलन की आवाज कभी पहाड़ की राजनीतिक चेतना का प्रतीक थी, वही आवाज चुनावी राजनीति में और कमजोर पड़ सकती है।

अब तक न यूकेडी चली, न बसपा का दांव, न आप का ‘माइल’

कार्यालय संवाददाता
देहरादून। उत्तराखंड की राजनीति का सबसे बड़ा विरोधाभास यह है कि जिस राज्य का जन्म क्षेत्रीय अस्मिता और अपने राजनीतिक भविष्य पर खुद फैसला लेने की आकांक्षा से हुआ, वहां ढाई दशक से अधिक समय बाद भी कोई क्षेत्रीय दल सत्ता का विकल्प नहीं बन सका। उत्तराखंड क्रांति दल ने अलग राज्य के लिए संघर्ष किया, बहुजन समाज पार्टी ने मैदानी जिलों में अपना जनाधार बनाया और आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के शासन मॉडल के सहारे प्रदेश में दस्तक दी। लेकिन विधानसभा की सत्ता तक पहुंचने की बारी आई तो मुकाबला भाजपा और कांग्रेस के बीच ही सिमट गया। यह महज छोटे दलों की चुनावी हार की कहानी नहीं है। यह उस राजनीतिक व्यवस्था की कहानी भी है, जिसमें मतदाता बदलाव चाहता है, लेकिन बदलाव के लिए वोट डालते समय अक्सर उसी दो-दलीय मुकाबले में लौट जाता है। सवाल है कि क्या उत्तराखंड में तीसरे विकल्प के लिए जमीन नहीं है, या जो दल उस जमीन पर खड़े होने का दावा करते रहे, वह उसे राजनीतिक ताकत में

बदलने में नाकाम रहे?

उत्तराखंड में 2००2 से 2०22 तक हुए पांच विधानसभा चुनावों के नतीजे इस राजनीतिक प्रवृत्ति की गवाही देते हैं। भाजपा और कांग्रेस का संयुक्त मत प्रतिशत लगातार बढ़ा, जबकि छोटे और क्षेत्रीय दलों के लिए विधानसभा में जगह बनाना कठिन होता गया। वर्ष 2००2 में दोनों राष्ट्रीय दलों को मिलाकर करीब 52 प्रतिशत मत मिले थे, जो 2०22 में बढ़कर लगभग 82 प्रतिशत हो गए। इन आंकड़ों में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि तीसरे विकल्प का संकट केवल सीटों का संकट नहीं है। छोटे दल चुनाव लड़ते रहे, मुद्दे उठाते रहे, लेकिन उनका समर्थन निर्णायक चुनावी शक्ति में नहीं बदल पाया। वर्ष 2०22 में 46 दल मैदान में थे, मगर विधानसभा में भाजपा, कांग्रेस और बसपा के अलावा केवल निर्दलीय उम्मीदवारों को जगह मिली। उत्तराखंड क्रांति दल के सामने सबसे बड़ी विडंबना यही है कि अलग राज्य की मांग को राजनीतिक स्वर देने वाला दल राज्य बनने के बाद सत्ता की मुख्य दावेदारी नहीं कर पाया। 2००2 में उसे चार सीटें मिलीं। 2००7 में तीन विधायक जीते।

लेकिन 2०12 के बाद उसका विधानसभा में प्रतिनिधित्व समाप्त हो गया। इसके पीछे कई कारण रहे। आंदोलनकारी संगठन से व्यापक चुनावी दल बनने की चुनौती, नेतृत्व के बीच मतभेद, बार-बार टूट और बदलते राजनीतिक समीकरणों ने उसकी ताकत को कमजोर किया। राज्य आंदोलन

◆उत्तराखंड में तीसरे विकल्प के बीच आंदोलन की जमीन पर दो दलों का कब्जा
◆राज्य बना, सरकारें बदलीं, लेकिन सत्ता की चाबी नहीं, यूकेडी में होती रही टूट
◆बसपा का सिमटता आधार व आप पार्टी की नाकामी की यह है असली कहानी

के दौरान गैरसैंण, स्थानीय रोजगार, पलायन और पहाड़ के संसाधनों पर अधिकार जैसे मुद्दे जनभावनाओं से जुड़े थे। लेकिन इन मुद्दों को बूथ स्तर के संगठन, मजबूत नेतृत्व और विश्वसनीय शासन के विकल्प में बदलना अलग चुनौती थी।

यूकेडी के सामने एक और मुश्किल थी। भाजपा ने अलग राज्य के समर्थन और राष्ट्रीय स्तर पर अपनी राजनीतिक ताकत के सहारे पहाड़ी मतदाताओं के बीच जगह बनाई। कांग्रेस के पास भी पुराना संगठन

और व्यापक चुनावी नेटवर्क था। ऐसे में यूकेडी जिस क्षेत्रीय अस्मिता की राजनीति पर आगे बढ़ सकता था, उसी के मुद्दों को दोनों राष्ट्रीय दल अपने चुनावी एजेंडे में शामिल करते रहे। नतीजा यह हुआ कि आंदोलन की विरासत यूकेडी के पास रही, लेकिन उसका राजनीतिक लाभ दूसरी पार्टियां उठाती रहीं।

उत्तराखंड में तीसरे विकल्प की चर्चा यूकेडी तक सीमित नहीं रही। बहुजन समाज पार्टी ने हरिद्वार, ऊधमसिंह नगर और मैदानी क्षेत्रों के कुछ हिस्सों में अपना प्रभाव बनाया। 2००2 में सात और 2००7 में आठ सीटें जीतकर उसने साबित किया कि भाजपा-कांग्रेस के बाहर भी मतदाताओं का एक आधार मौजूद है। लेकिन 2०12 में उसकी सीटें घटकर तीन रह गईं, 2०17 में वह खाता नहीं खोल सकी और 2०22 में दो सीटों पर सिमट गई। बसपा की चुनौती यह रही कि उसका प्रभाव कुछ सामाजिक और भौगोलिक क्षेत्रों में तो दिखाई दिया, लेकिन वह पूरे प्रदेश में समान ताकत वाला विकल्प नहीं बन पाई। उत्तराखंड की राजनीति में पर्वतीय और मैदानी क्षेत्रों के

सवाल अलग-अलग रूप में सामने आते हैं। ऐसे में किसी दल को राज्यव्यापी पहचान बनाने के लिए स्थानीय सामाजिक समीकरणों से आगे बढ़कर साझा राजनीतिक कार्यक्रम तैयार करना पड़ता है। बसपा के अनुभव से यह भी स्पष्ट होता है कि कुछ सीटों पर प्रभावशाली होना और सरकार बनाने लायक जनाधार हासिल करना दो अलग बातें हैं। सीमित क्षेत्रों में समर्थन होने के बावजूद जब पार्टी का राज्यव्यापी संगठन कमजोर पड़ता है, तो उसका चुनावी प्रभाव सत्ता के समीकरण बदलने की क्षमता नहीं बना पाता।

आम आदमी पार्टी ने उत्तराखंड में शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली और दिल्ली के शासन मॉडल को आधार बनाकर राजनीतिक जमीन तैयार करने की कोशिश की। पार्टी ने 2०22 के विधानसभा चुनाव में सभी 7० सीटों पर उम्मीदवार उतारे, लेकिन एक भी सीट नहीं जीत सकी। यह नतीजा बताता है कि किसी दूसरे राज्य में सफल राजनीतिक मॉडल को उत्तराखंड में दोहराना आसान नहीं है। यहां मतदाता केवल सेवाओं और सुविधाओं की घोषणाओं से

कुंभ के लिए 35०5 पुलिसकर्मियों को दिया प्रशिक्षण

हरिद्वार(आरएनएस)। कुंभ मेला 2०27 में भीड़ प्रबंधन और सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुलिसकर्मियों को प्रशिक्षित किया जा रहा है। चार माह से चल रहे प्रशिक्षण के 13 चरणों में 35०5 पुलिसकर्मियों को मेले की व्यवस्थाओं और चुनौतियों से निपटने के तरीके बताए गए। सशस्त्र प्रशिक्षण केंद्र हरिद्वार में प्रशिक्षण के 13वें चरण के समापन पर पुलिस महानिरीक्षक अनंत शंकर ताकवाले ने इंडियन रेडक्रॉस उत्तराखंड के चेयरमैन डॉ. नरेश चौधरी के योगदान की सराहना की। पुलिस विभाग के निर्देशन और कुंभ मेला पुलिस के संयोजन में पिछले चार माह से विभिन्न चरणों में प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसमें पूर्व में कुंभ और अर्धकुंभ मेले में ड्यूटी कर चुके अनुभवी विशेषज्ञों के माध्यम से पुलिसकर्मियों को मेले की व्यवस्थाओं और चुनौतियों से निपटने के लिए तैयार किया जा रहा है।

डॉ. नरेश चौधरी ने सभी 13 चरणों में पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया। इसमें कुंभ मेले का इतिहास, भीड़ नियंत्रण, अखाड़ों की परंपराएं, पेशवाई, शाही स्नान और अमृत स्नान की व्यवस्थाओं की जानकारी दी गई। इसके साथ ही पूर्व में आयोजित कुंभ मेलों के दौरान हुई महत्वपूर्ण घटनाओं, उनसे संबंधित जांच आयोगों की रिपोर्ट और उनकी सिफारिशों के अनुपालन पर भी चर्चा की गई। प्रशिक्षण के दौरान पुलिसकर्मियों को स्थानीय नागरिकों, व्यापारियों, साधु-संतों, आश्रमों, धर्मशालाओं, होटलों, स्वयंसेवी संस्थाओं और अन्य विभागों के साथ बेहतर समन्वय स्थापित करने की आवश्यकता बताई गई।

डॉ. चौधरी ने बड़े स्नान पर्वों और आयोजनों के दौरान चार दशकों में निभाई गई जिम्मेदारियों के अनुभव साझा करते हुए पुलिसकर्मियों को व्यावहारिक पहलुओं से अवगत कराया। डॉ. नरेश चौधरी ने कहा कि कुंभ मेला 2०27 में पिछले आयोजनों की तुलना में अधिक श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है।

मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से स्नान पर्वों के प्रति बढ़ती जागरूकता के कारण प्रमुख स्नान तिथियों पर श्रद्धालुओं की संख्या अधिक रह सकती है। ऐसे में भीड़ नियंत्रण, सुरक्षा और व्यवस्थाओं को लेकर पुलिसकर्मियों का व्यावहारिक और मानसिक रूप से तैयार रहना जरूरी है। पुलिस महानिरीक्षक अनंत शंकर ताकवाले और कुंभ मेला के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आयुष अग्रवाल ने सभी 13 चरणों में 35०5 पुलिसकर्मियों को प्रशिक्षण देने के लिए डॉ. चौधरी की सराहना करते हुए उनका आभार जताया।

अब तक न यूकेडी चली, न बसपा का..

◀ पृष्ठ 3 का शेष

प्रभावित नहीं होता। स्थानीय नेतृत्व, सामाजिक संपर्क, क्षेत्रीय समस्याओं की समझ और चुनावी संगठन भी महत्वपूर्ण हैं। पहाड़ के दूरस्थ गांवों से लेकर हरिद्वार और ऊधमसिंह नगर के मैदानी क्षेत्रों तक अलग-अलग अपेक्षाओं को जोड़ना किसी भी नए दल के लिए बड़ी चुनौती है। आप की चुनौती यह भी थी कि भाजपा और कांग्रेस के बीच पहले से मौजूद मुकाबले में उसे अपनी अलग पहचान बनानी थी। चुनाव के दौरान प्रचार और संगठन खड़ा करना एक बात है, लेकिन वर्षों तक गांवों, कस्बों और स्थानीय मुद्दों के बीच मौजूद रहना दूसरी बात। 2०22 का परिणाम दिखाता है कि राजनीतिक पहचान को मतों और सीटों में बदलने के लिए केवल प्रचार पर्याप्त नहीं था।

इस सवाल का जवाब इतना सरल नहीं है कि उत्तराखंड का मतदाता तीसरे दल को पसंद नहीं करता। बसपा की शुरुआती सफलताएं और यूकेडी की कुछ सीटें बताती हैं कि छोटे दलों के लिए जगह रही है। लेकिन चुनावी मुकाबला जैसे-जैसे भाजपा और कांग्रेस के बीच केंद्रित हुआ, वैसे-वैसे छोटे दलों के सामने एक कठिन गणित खड़ा हो गया। मतदाता अक्सर उस उम्मीदवार को प्राथमिकता दे सकता है जिसे वह जीतने की स्थिति में देखता है। यदि किसी क्षेत्र में मुकाबला भाजपा और कांग्रेस के बीच माना जा रहा हो, तो तीसरे दल को पसंद करने वाला मतदाता भी अपने वोट के संभावित परिणाम पर विचार कर सकता है। इस तरह छोटे दलों के लिए समर्थन होने के बावजूद वह सीट जीतने की स्थिति तक नहीं पहुंचता। इसे चुनावी ध्रुवीकरण और रणनीतिक मतदान के रूप में समझा जा सकता है।

2०27 के विधानसभा चुनाव से पहले तीसरे विकल्प के सामने सबसे बड़ा सवाल यह नहीं होना चाहिए कि भाजपा और कांग्रेस से कितनी नाराजगी है। असली सवाल यह होना चाहिए कि वह इस नाराजगी को विश्वसनीय राजनीतिक विकल्प में कैसे बदलेगा। इसके लिए तीन बुनियादी शर्तें जरूरी हैं। पहली, प्रदेशव्यापी संगठन और स्थानीय नेतृत्व। दूसरी, रोजगार, पलायन, खेती, शिक्षा, स्वास्थ्य और जमीन जैसे मुद्दों पर स्पष्ट कार्यक्रम। तीसरी, चुनाव के बाद भी जनता के बीच सक्रिय रहने की राजनीतिक इच्छाशक्ति। किसी दल को केवल चुनाव के समय दिखाई देने से राज्यव्यापी जनाधार नहीं मिलता। उत्तराखंड में तीसरी ताकत की सबसे बड़ी विफलता यह नहीं कि उसे कभी मौका नहीं मिला, बल्कि यह है कि जो मौके मिले, उन्हें स्थायी जनाधार में बदलने की क्षमता विकसित नहीं हो सकी। भाजपा और कांग्रेस की पकड़ का कारण केवल मतदाता की पसंद नहीं, बल्कि संगठन, संसाधन, नेतृत्व और चुनावी रणनीति का है।

वैधानिक सूचना

सुविज्ञ पाठकों से आग्रह है कि इस समाचार पत्र में प्रकाशित किसी भी विज्ञापन में दिए गए तथ्यों, शर्तों और दावों के प्रति वह खुद भी आश्वस्त हो लें। पाठकों से आग्रह है कि वह प्रकाशित विज्ञापन से प्रभावित होकर कोई कदम उठाने से पहले अपने स्तर पर भी स्वयं के संतुष्ट होने तक संपूर्ण व्यावहारिक जानकारी कर लें। भविष्य में किसी भी प्रकाशित विज्ञापन व लेख में निहित दावों या शर्तों को लेकर पाठकगण को कोई असुविधा या परेशानी होती है तो *सांध्य दैनिक दून वैली मेल* के मुद्रक, प्रकाशक या सम्पादक की कोई जवाबदेही नहीं होगी।

—प्रबंधक विज्ञापन

किडनी से जुड़ी बीमारी वालों को संतरा खाने से परहेज करना चाहिए

सर्दी का मौसम आते ही संतरा मार्केट से सजा हुआ होता है। हेल्थ एक्सपर्ट भी अक्सर कहते हैं कि सीजनल फल जरूर खाना चाहिए। क्योंकि शरीर को जरूरी पोषक तत्व मिल जाते हैं। एक वक्त था जब संतरा सिर्फ सर्दियों में मिलता था लेकिन अब तो संतरा पूरे साल मिलता है। संतरा हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छा होता है क्योंकि इसमें विटामिन सी होता है। वहीं डॉक्टर्स इन बीमारी वाले लोगों को संतरा खाने से मना करते हैं।

किडनी

हेल्थ एक्सपर्ट के मुताबिक हृदय से ज्यादा संतरा खाने से किडनी पर बहुत खतरनाक असर पड़ता है। जिसकी वजह से किडनी की बीमारी हो सकती है। जिन लोगों को अगर पहले से है तो ट्रिगर कर सकता है। किडनी स्टोन या किडनी से जुड़ी बीमारी वाले को संतरा खाने से परहेज करना चाहिए। क्योंकि इसमें भरपूर मात्रा में पोटेशियम होता है जो कि किडनी के लिए नुकसानदायक होता है।

सिट्रस एलर्जी

कई लोगों को खट्टा फल खाने से एलर्जी की परेशानी शुरू हो जाती है। जिन लोगों को एलर्जी की दिक्रत है वह अगर खट्टा फल नींबू या संतरा खाएंगे तो उनकी एलर्जी बढ़ सकती है। संतरा में विटामिन सी, एंटीऑक्सिडेंट्स, फाइबर और कई



मिनरल्स प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। ये स्ट्रॉबेरी की तरह ही एंटीऑक्सिडेंट से भरपूर होते हैं। यदि आप कोलेस्ट्रॉल की बीमारी से जूझ रहे हैं तो आपको संतरा खाना चाहिए। संतरा खाने एलडीएल यानि खराब कोलेस्ट्रॉल कम होता है।

यदि आप कोलेस्ट्रॉल की बीमारी से जूझ रहे हैं तो आपसंतरा आमतौर पर स्वास्थ्यवर्धक होता है, लेकिन इसके अत्यधिक सेवन से फाइबर की मात्रा के कारण पाचन संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। इसके अतिरिक्त, साइट्रस एलर्जी या किडनी की समस्याओं जैसी कुछ चिकित्सीय स्थितियों वाले व्यक्तियों को

इसका सेवन कम करना चाहिए। ज्यादा संतरा खाने से उल्टी, मतली, सिरदर्द जैसी गंभीर दिक्रत भी पैदा हो सकती है।

किन लोगों को संतरा नहीं खाना चाहिए?

जिन लोगों को किडनी और लिवर की बीमारी है उन्हें संतरा नहीं खाना चाहिए। क्योंकि संतरे में पोटेशियम की मात्रा काफी ज्यादा होती है। साइट्रस एलर्जी वाले लोगों को हर रोज संतरा खाना चाहिए। हमेशा किसी स्वास्थ्य देखभाल पेशेवर से परामर्श लें। को संतरा खाना चाहिए। संतरा खाने एलडीएल यानि खराब कोलेस्ट्रॉल कम होता है।

केला एक प्रकृति का सुपरफूड, जो हर उम्र में रखे सेहत का ख्याल

केला भारत के सबसे प्राचीन और पोषक फलों में से एक माना जाता है। यह सिर्फ स्वादिष्ट फल नहीं है, बल्कि एक ऊर्जा-पोषण-उपचार त्रिवेणी है। आयुर्वेद के अनुसार, केला मधुर, गुरु, शीतल, बल्य, पित्त-शामक, वात-नाशक और ओज-वर्धक होता है, इसलिए इसे सर्वगुण संपन्न फल भी कहा जाता है।

यह सस्ता, आसानी से उपलब्ध और हर आयु के लिए सुरक्षित है। खासकर बच्चों, छात्रों, एथलीट्स, बुजुर्गों, कमजोर व्यक्तियों, एनीमिया और पाचन कमजोरियों

वाले लोगों के लिए केला तुरंत ऊर्जा देने वाला सुपरफूड है। केला खाने के कई खास तरीके हैं।

अगर हल्की गैस, कब्ज या अपच हो तो केले पर चुटकीभर काला नमक डालकर खाने से आमपित्त शांत होता है और अग्नि संतुलित रहती है। थकावट या कमजोरी में गुनगुना दूध और केला अच्छा ऑप्शन है। यह मांसपेशियों के लिए पोषक माना जाता है। पेट की जलन या अल्सर में थोड़ी मिश्री के साथ केला खाना अच्छा होता है। कमजोरी महसूस हो तो केला और

शहद का सेवन करें, यह शरीर में ओज बढ़ाता है और इम्युनिटी मजबूत करता है। नींद न आने की समस्या हो तो केला और गर्म दूध बेहद फायदेमंद है, क्योंकि इसमें ट्रिप्टोफैन और मेलाटोनिन मिलकर अच्छी नींद लाते हैं। यह महिलाओं व छात्रों के लिए विशेष लाभकारी है। एथलीट्स के लिए केला काफी फायदेमंद होता है और थकान तुरंत दूर करता है। त्वचा के लिए पका केला और दही का फेस पैक बनाकर लगाने से नमी, निखार और कोमलता आती है।

शब्द सामर्थ्य -069

(भागवत साहू)

बाएं से दाएं

1. तकलीफ, कष्ट, कठिनाई, परेशानी 3. सरल, सहज 6. ज्ञान प्राप्त करना, शिक्षा लेना 7. विवश, लाचार 8. अत्यधिक ठंडा, सुस्त 9. अच्छे ढंग में गाया जाने वाला सुंदर गीत 11. सूर्य, सूरज 13. वस्त्र आदि धारण कराना 15. अप्रसन्न,

नाखुश 16. खिंचाव, आकर्षण शक्ति (उ.) 18. एक रंग, आसमानी रंग 22. सेवा-सत्कार, आवभगत 23. सर्प, सांप, लकड़ी आदि की मूर्ति बनाना।

ऊपर से नीचे

1. हृदय, उर 2. शिष्टता, भद्रता, विवेक (उ.) 3. अंततः, अंततोगत्वा

1		2		3		4		5
						6		
	7							
8						9	10	
				11	12			
13			14		15			
			16	17			18	19
	20					21		
22						23		

शब्द सामर्थ्य क्रमांक 68 का हल

चु	स्त		मु		सं	स्था	न	
ग		म	र्दा	न	गी		त	म
ली	प	ना			त	न		
	ना	ना					ज	
मा	ह		रा		सा	ज	न	
न		स	ह	दे	व		म	द
व		म		व	न	ज		ल
ता	क	त	व	र		मी		द
	ल	ल	क		क	र	त	ल

रणवीर कपूर-यश की रामायण पार्ट 2 से टकराएगी प्रभास की फिल्म स्पिरिट !

रिबेल स्टार प्रभास के फैस के लिए एक गुड न्यूज है. प्रभास की आगामी फिल्म स्पिरिट की नई रिलीज डेट से पर्दा हट गया है. मेकर्स ने स्पिरिट की नई रिलीज डेट का एलान किया है. यह फिल्म रणवीर कपूर और यश की रामायण पार्ट 2 के आमने-सामने आ गई है, जिससे बॉक्स ऑफिस पर एक जोरदार मुकाबला देखने को मिल सकता है.

संदीप रेड्डी वांगा ने फैस को हिंट दिया कि वह स्पिरिट फिल्म से प्रभास का एक नया लुक और फिल्म की रिलीज डेट सामने लाएंगे. उन्होंने एक्स (पहले ट्विटर) हैंडल पर एक पोस्ट शेयर और लिखा, डियर प्रभास अन्ना के फैस, मैं एक नया पोस्टर पेश करना चाहता हूं, जिसमें चश्मे के पीछे छिपे प्रभास नजर आ रहे हैं और साथ ही नई रिलीज डेट भी दी गई है. बस कुछ ही मिनट... स्पिरिट - एक बुरी आदत, भारत के सबसे बड़े सुपरस्टार.

कुछ मिनट बाद संदीप ने प्रभास का नया पोस्टर साझा करते हुए स्पिरिट की नई रिलीज डेट का एलान किया. पोस्टर में प्रभास ब्लैक सनग्लासेस, मैचिंग कैप और शर्ट में नजर आ रहे हैं. उनका चेहरा पूरा शांत और गंभीर दिखाई दे रहा है. प्रभास के इस लुक के साथ वांगा ने बताया कि स्पिरिट अब दिवाली के मौके पर 29 अक्टूबर, 2027 को रिलीज होगी.

प्रभास और संदीप रेड्डी वांगा की आने वाली एक्शन थ्रिलर फिल्म पहले 5 मार्च 2027 को सिनेमाघरों में आने वाली थी, अब 29 अक्टूबर 2027 को दिवाली के मौके पर दुनिया भर में रिलीज होगी. ऐसे में इसे रामायण पार्ट 2 से टकरा मिल सकती है. इस फिल्म में एनिमल फेम रणवीर कपूर राम के किरदार में, साई पल्लवी सीता के रूप में और यश रावण की भूमिका में नजर आएंगे.

बता दें, रामायण के दूसरे भाग के दिवाली 2027 में रिलीज होने का एलान काफी पहले ही कर दिया गया था, हालांकि अभी तक कोई पक्की तारीख तय नहीं हुई है. दोनों ही फिल्मों को लेकर काफी चर्चा है, ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि बॉक्स ऑफिस पर इनका टकराव कैसा रहता है. फिल्म के एलान के बाद इस साल 1 जनवरी को एक्टर का फर्स्ट-लुक पोस्टर जारी किया गया, जिसमें प्रभास लंबे बाल और शरीर पर चोट के निशान के साथ एक रफ लुक में दिखे. संदीप रेड्डी वांगा की लिखित और निर्देशित स्पिरिट को टी-सीरीज और भद्रकाली पिक्चर्स मिलकर प्रोड्यूस कर रहे हैं.

सनी देओल की फिल्म सूर्या: अंत से आरंभ तक' का ऐलान

बॉलीवुड अभिनेता सनी देओल की आगामी फिल्म %सूर्या'अंत से आरंभ तक' की आधिकारिक घोषणा कर दी गई है। यह एक अपराध और रोमांच पर आधारित एक्शन फिल्म होगी, जिसका निर्देशन एम. पद्मकुमार कर रहे हैं। फिल्म का निर्माण एमएम मूवीज के बैनर तले किया जा रहा है। निर्माताओं ने फिल्म का पहला दृश्य-गत पोस्टर जारी करने के साथ इसकी प्रदर्शन तिथि का भी खुलासा किया है। फिल्म 20 नवंबर 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

%सूर्या'अंत से आरंभ तक' की कहानी एक ऐसे व्यक्ति के इर्द-गिर्द घूमती है, जो अनसुलझे सवालों और दबी हुई सच्चाइयों के बीच फंस जाता है। कहानी में अपराध, रहस्य और रोमांच के कई पहलू देखने को मिलेंगे। हालांकि, निर्माताओं ने अभी फिल्म की कहानी के बारे में विस्तार से जानकारी साझा नहीं की है।

फिल्म के पहले दृश्य-गत पोस्टर में सनी देओल गंभीर और प्रभावशाली अंदाज में नजर आ रहे हैं। उनकी तीखी नजरें और व्यक्तित्व उनके किरदार के भीतर चल रहे संघर्ष की झलक देते हैं। पोस्टर से संकेत मिलता है कि फिल्म में उनका सामना अतीत से जुड़े रहस्यों और कई अनसुलझे सवालों से होगा।

फिल्म में सनी देओल के साथ रवि किशन, प्रज्ञा जायसवाल और जिशु सेनगुप्ता भी महत्वपूर्ण भूमिकाओं में दिखाई देंगे। इन कलाकारों की मौजूदगी से फिल्म की कहानी में विविधता आने की उम्मीद है। हालांकि, उनके किरदारों से जुड़ी विस्तृत जानकारी अभी सामने नहीं आई है।

निर्माताओं ने %सूर्या'अंत से आरंभ तक' की रिलीज के लिए 20 नवंबर 2026 की तारीख तय की है। फिल्म के पहले पोस्टर के जारी होने के बाद से ही इसे लेकर दर्शकों की उत्सुकता बढ़ गई है। अब दर्शकों को फिल्म के अगले प्रचार अभियान, कहानी से जुड़े खुलासों और अन्य झलकियों का इंतजार रहेगा।

सनी देओल की इस फिल्म में एक्शन, अपराध और रहस्य का मेल देखने को मिलेगा। फिल्म की सफलता को लेकर अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन इसकी घोषित रिलीज तारीख और कलाकारों की सूची ने इसे आगामी फिल्मों में शामिल कर दिया है।



डायबिटीज मेरी जिंदगी का हिस्सा है, पूरी पहचान नहीं: ऐश्वर्या सखुजा

सास बिना ससुराल, मैं ना भूलूंगी, त्रिदेवियां और रिश्ता डॉट कॉम जैसे शो में नजर आ चुकीं टीवी एक्ट्रेस ऐश्वर्या सखुजा पिछले 10 साल से टाइप-1 डायबिटीज से जूझ रही हैं। इस बीमारी को लेकर उन्होंने बताया कि उन्हें शुरुआत में गलत बीमारी बताई गई थी। बाद में पता चला कि वह टाइप-1 डायबिटीज से जूझ रही हैं। एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर कर बताया कि पिछले 10 साल उनके लिए इंसुलिन लेने, अपनी बॉडी को समझने और लाइफस्टाइल में बदलाव करने का सफर रहा है। डायबिटीज को मैनेज करना कई बार थका देने वाला रहता है। ऐश्वर्या ने इंस्टाग्राम पर लिखा, 10 साल पहले मेरी बीमारी का गलत पता लगाया गया था। जब तक मुझे समझ आया कि मेरी बॉडी के साथ क्या हो रहा है, तब तक मुझे अंदाजा भी नहीं था कि मेरी जिंदगी इस तरह बदलने वाली है और मुझे हर दिन इसके साथ तालमेल बिठाना पड़ेगा। आज टाइप-1 डायबिटीज के साथ जीते हुए मुझे 10 साल पूरे हो गए हैं।

उन्होंने आगे लिखा, 10 साल से इंसुलिन ले रही हूं। 10 साल से अपनी बॉडी को समझ रही हूं। इस दौरान कई उतार-चढ़ाव आए, बहुत कुछ सीखा, कई बार निराशा हुई और धीरे-धीरे चीजों को समझना पड़ा। इन 10 सालों में मैंने अपना ख्याल रखने की कोशिश की है। उन दिनों में भी जब खुद की देखभाल करना किसी फुल-टाइम जॉब जैसा लगता है।

एक्ट्रेस ने लिखा, मैंने एक्सरसाइज की है और अपने खाने को लेकर भी ध्यान



रखा है। मैंने सीखा है कि अपना ख्याल रखने का मतलब परफेक्ट होना नहीं है। इसका मतलब है बार-बार कोशिश करते रहना। इस सफर में मुझे अपनी बॉडी के प्रति थोड़ा और नरम होना भी सीखना पड़ा है। उस बॉडी के प्रति, जिसे इंसुलिन की जरूरत होती है।

उन्होंने लिखा, मैं डायबिटीज को खूबसूरत बनाकर पेश नहीं करूंगी। यह थका देने वाली, कई बार नाइंसाफी जैसी लगने वाली और बहुत मेहनत मांगने वाली बीमारी हो सकती है। लेकिन यह मेरी जिंदगी का एक हिस्सा है, लेकिन मेरी पूरी

पहचान नहीं।

अपनी पोस्ट के आखिर में ऐश्वर्या ने टाइप-1 डायबिटीज के साथ जी रहे लोगों को भी हिम्मत दी। उन्होंने लिखा, अपनी सेहत का ध्यान रखने के लिए हर समय परफेक्ट होना जरूरी नहीं है। जरूरी यह है कि इंसान अपनी क्षमता के मुताबिक लगातार कोशिश करता रहे। ब्लड ग्लूकोज मॉनिटर पर दिखने वाले नंबरों से कहीं ज्यादा चीजें डायबिटीज से जुड़ी होती हैं। मुझे उम्मीद है कि आने वाले सालों में मैं खुद के प्रति और ज्यादा धैर्य और नरमी रख पाऊंगी।

मां बनने के बाद काम पर लौटीं दिव्यांका त्रिपाठी



अभिनेत्री दिव्यांका त्रिपाठी इन दिनों पति विवेक दहिया के साथ कपल रियलिटी शो पति पत्नी और पंगा में नजर आ रही हैं। अभिनेत्री ने हाल ही में जुड़वा बच्चों के जन्म के बाद काम करने की चुनौतियों पर बात की। अभिनेत्री ने बताया कि बच्चों को कुछ समय के लिए अकेले छोड़ना बहुत मुश्किल हो गया है, क्योंकि वे बड़े हो रहे हैं और अपने आसपास की चीजों को एक्सप्लोर कर रहे हैं। अभिनेत्री ने यह भी बताया कि जैसे-जैसे बच्चे बड़े हो रहे हैं, उनकी देखभाल का अनुभव भी बदल रहा है। दिव्यांका त्रिपाठी ने कहा, इस स्टेज पर बच्चों को संभालना आसान है, क्योंकि अभी बस वह सोते और खाते हैं लेकिन मुझे पता है कि अब उनके घुटनों के बल

चलने का समय आएगा। उन्होंने धीरे-धीरे खुद को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया है। मेरे लिए तो उन्हें दो से चार मिनट के लिए भी अकेला छोड़ना मुश्किल है। इसलिए मुझे उन्हें सेट पर भी साथ ले जाना पड़ता है। हालांकि, यह आसान नहीं है।

अभिनेत्री ने बताया कि लोगों को इस बात पर भी हैरानी होती है कि वो इतनी जल्दी काम पर कैसे लौट आईं। उन्होंने कहा, मैं हमेशा कहती हूं कि महिलाएं ऐसे ही बाउंस बैक नहीं कर लेतीं। देखिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। भले ही हम एक्ट्रेस कैमरे के सामने हंसती-मुस्कराती दिखती हैं लेकिन शरीर के अंदर दर्द, थकान और दिमाग में कन्फ्यूजन जैसा रहता है।

अभिनेत्री का कहना है कि उन्हें काम

पर लौटने की जरूरत नहीं थी लेकिन वे फिर भी लौटीं। क्योंकि एक मां के लिए घर पर बैठना भी आसान नहीं और काम करना भी आसान नहीं।

उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि मां बनने के बाद काम पर लौटने को लेकर महिलाओं की तुलना एक-दूसरे से नहीं करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हर किसी की परिस्थितियां अलग होती हैं, इसलिए महिलाओं को किसी और के अनुभव के दबाव में आने के बजाय अपनी जर्नी पर भरोसा करना चाहिए। उन्होंने कहा, मैं ये इसलिए कह रही हूं ताकि कोई भी एक महिला की तुलना दूसरी से न करे और ये न कहे कि अरे दिव्यांका ने कर लिया। नहीं, ये सबके लिए मुश्किल है। हर कोई अपने हिसाब से काम पर लौटता है। तो आप भी अपनी गति से चलें और मैं भी अपनी गति से चल रही हूं।

इसी के साथ ही, अभिनेत्री ने परिवार और पति का भी शुक्रिया अदा किया, जिन्होंने उनके मां बनने के साथ-साथ काम को भी संभालने का हौसला दिया। अभिनेत्री ने कहा, मैं बहुत हिम्मत दिखा रही हूं लेकिन इसके पीछे की वजह विवेक हैं, वे हर पल मेरे साथ खड़े रहते हैं। मेरी फैमिली मुझसे कहती है, तू कर लेगी। ये मत सोचती रह कि इंतजार करना चाहिए या नहीं, अगर इंतजार करती रही तो कभी शुरू ही नहीं कर पाएंगी। मुझे भी लगता है कि काम करना हमारे मेंटल हेल्थ के लिए अच्छा है। आपके साथ रहना मेरे मेंटल हेल्थ के लिए अच्छा है।

सपनों के पहाड़ और सियासत के दावों की अधूरी उम्मीदें

कार्यालय संवाददाता
देहरादून। उत्तराखंड नौ नवंबर 2००० को अलग राज्य बना तो उम्मीद थी कि पहाड़ की भौगोलिक परिस्थितियों, सामाजिक जरूरतों और स्थानीय आकांक्षाओं के अनुरूप विकास का नया माडल तैयार होगा। रोजगार के लिए पलायन रुकेगा, गांवों तक बुनियादी सुविधाएं पहुंचेंगी, गैरसैंण को उसकी राजनीतिक पहचान मिलेगी और प्राकृतिक संसाधनों से संपन्न प्रदेश के लोगों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। लेकिन राज्य गठन के 26वें वर्ष में प्रवेश के साथ सवाल यह है कि भाजपा और कांग्रेस की सरकारों ने इन उम्मीदों को कितना पूरा किया? दोनों दलों को सत्ता में रहने के अवसर मिले, दोनों ने विकास के दावे किए, लेकिन पहाड़ की समस्याएं आज भी प्रदेश की राजनीति के केंद्र में हैं।

उत्तराखंड के गठन को लेकर भाजपा और कांग्रेस के बीच श्रेय लेने की राजनीति लंबे समय से जारी है। भाजपा पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के कार्यकाल में राज्य गठन को अपनी बड़ी उपलब्धि बताती है। वहीं, कांग्रेस राज्य आंदोलन में अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं की भूमिका तथा राज्य गठन से पहले और बाद में किए गए प्रयासों को सामने रखती है। हालांकि, उत्तराखंड का निर्माण किसी एक दल की राजनीतिक उपलब्धि भर नहीं था। इसके पीछे दशकों का संघर्ष, उत्तराखंड क्रांति दल की भूमिका, आंदोलनकारी संगठनों का योगदान और हजारों लोगों का त्याग था। राज्य गठन के राजनीतिक श्रेय से आगे बढ़कर असली

सवाल यह है कि सत्ता में आने के बाद दोनों राष्ट्रीय दलों ने आंदोलन की मूल आकांक्षाओं को कितना महत्व दिया।

राज्य गठन के बाद वर्ष 2००2 में हुए पहले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 36 सीटें जीतकर सरकार बनाई। नारायण दत्त तिवारी के नेतृत्व वाली सरकार ने औद्योगिक विकास को गति देने और प्रदेश में निवेश आकर्षित करने पर जोर दिया। हरिद्वार, देहरादून और ऊधमसिंह नगर के औद्योगिक क्षेत्रों में निवेश की संभावनाओं को विस्तार मिला। औद्योगिक गतिविधियों ने रोजगार और आर्थिक विकास के नए अवसर पैदा किए। तिवारी सरकार का कार्यकाल इसलिए भी उल्लेखनीय रहा कि वह प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे, जिन्होंने अपना पांच वर्षीय कार्यकाल पूरा किया।

लेकिन औद्योगिक विकास की चमक पहाड़ के दूरस्थ गांवों तक समान रूप से नहीं पहुंच सकी। मैदानी क्षेत्रों में उद्योगों के विस्तार के मुकाबले पर्वतीय जिलों में रोजगार के पर्याप्त अवसर पैदा करना चुनौती बना रहा। यही असंतुलन आगे चलकर पलायन और क्षेत्रीय विकास की बहस का प्रमुख मुद्दा बना। कांग्रेस को यह जवाब देना होगा कि उसके शासनकाल में शुरू हुई विकास की प्रक्रिया को पहाड़ी अर्थव्यवस्था, कृषि, बागवानी और स्थानीय रोजगार से जोड़ने के लिए पर्याप्त प्रयास क्यों नहीं हो सके। वर्ष 2०12 में कांग्रेस फिर सत्ता में लौटी। विजय बहुगुणा के बाद हरीश रावत ने मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी संभाली। इस दौरान राजनीतिक अस्थिरता, वर्ष 2०13 की केदारनाथ आपदा के बाद पुनर्निर्माण और वर्ष 2०16 के राजनीतिक

संकट ने सरकार को लगातार चुनौती दी। आपदा प्रभावित क्षेत्रों का पुनर्वास और चारधाम यात्रा व्यवस्था का पुनर्गठन महत्वपूर्ण विषय रहे। मगर सरकार की उपलब्धियों के साथ नेतृत्व संबंधी विवाद और राजनीतिक अस्थिरता भी कांग्रेस की छवि पर असर डालते रहे।

◆25 साल में भाजपा और कांग्रेस का हिसाब, विकास की रफ्तार और वादों की कसौटी
◆कभी भाजपा तो कभी कांग्रेस के हाथ में सत्ता, फिर भी पहाड़ के मूल सवाल बरकरार
◆2०27 के चुनाव से पहले दलों के सामने अपने कामकाज का हिसाब देने की चुनौती

भाजपा ने वर्ष 2००7 में सरकार बनाई। बीसी खंडूड़ी और रमेश पोखरियाल निशंक के नेतृत्व में सड़क, आधारभूत ढांचे और प्रशासनिक सुधारों को लेकर कई घोषणाएं हुईं। हालांकि, मुख्यमंत्री बदलने की राजनीति ने सरकार की स्थिरता पर सवाल खड़े किए। वर्ष 2०12 के चुनाव में भाजपा सत्ता से बाहर हो गई।

वर्ष 2०17 में भाजपा ने 7० सदस्यीय

विधानसभा में 57 सीटें जीतकर ऐतिहासिक बहुमत हासिल किया। इसके बाद त्रिवेन्द्र सिंह रावत, तीरथ सिंह रावत और पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में सरकार चली। वर्ष 2०22 में भाजपा ने 47 सीटें जीतकर लगातार दूसरी बार सरकार बनाने का इतिहास रचा। इस दौरान सड़क और राजमार्ग परियोजनाओं, चारधाम यात्रा से जुड़े बुनियादी ढांचे, पर्यटन, धार्मिक स्थलों के विकास और निवेश आकर्षित करने पर विशेष जोर दिया गया। धामी सरकार ने समान नागरिक संहिता लागू करने, भर्ती परीक्षाओं में नकल के विरुद्ध सख्त कानून बनाने और महिलाओं के लिए सरकारी नौकरियों में क्षैतिज आरक्षण जैसे कदमों को अपनी प्रमुख उपलब्धियों में शामिल किया है। सरकार का दावा है कि इन फैसलों से सुशासन, सामाजिक सुरक्षा और रोजगार व्यवस्था को मजबूती मिली है।

लेकिन भाजपा के सामने भी कई सवाल हैं। बड़े बुनियादी ढांचा प्रकल्पों और पर्यटन विस्तार के बीच पर्वतीय गांवों में स्थायी रोजगार, स्वास्थ्य सुविधाओं, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और पलायन की समस्या का समाधान कितना हुआ? भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताओं को लेकर युवाओं में पैदा हुए असंतोष ने सरकार की परीक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े किए। इसके अलावा भू-कानून, जमीन की खरीद, पर्यावरणीय संतुलन और आपदा प्रबंधन जैसे मुद्दे भी सरकार से ठोस जवाब मांगते हैं।

भाजपा और कांग्रेस के शासनकाल की तुलना करते समय यह भी देखना होगा

कि राज्य की अर्थव्यवस्था में विस्तार हुआ है और बुनियादी सुविधाओं का दायरा बढ़ा है, लेकिन विकास का लाभ सभी क्षेत्रों और वर्गों तक समान रूप से पहुंचाना अब भी चुनौती है। उद्योग, पर्यटन और निर्माण गतिविधियों से आर्थिक अवसर बढ़े हैं, मगर पर्वतीय क्षेत्रों में रोजगार का स्थायी आधार तैयार करना अपेक्षित गति से आगे नहीं बढ़ पाया। शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में संस्थानों की मौजूदगी के साथ उनकी गुणवत्ता, विशेषज्ञों की उपलब्धता और दूरस्थ गांवों तक पहुंच का सवाल भी बना हुआ है। पलायन केवल आर्थिक समस्या नहीं, बल्कि प्रदेश की सामाजिक और सांस्कृतिक संरचना से जुड़ा प्रश्न है। गांवों से युवाओं का बाहर जाना खेती, स्थानीय बाजारों, पारंपरिक ज्ञान और सामुदायिक जीवन को प्रभावित करता है। दोनों दलों ने पलायन रोकने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की घोषणाएं की हैं, लेकिन जनता के सामने कसौटी घोषणाएं नहीं, परिणाम हैं।

उत्तराखंड की राजनीति का सबसे बड़ा विरोधाभास यही है कि भाजपा और कांग्रेस सत्ता के लिए बारी-बारी से जनादेश हासिल करती रही हैं, लेकिन राज्य आंदोलन के कई मूल सवाल आज भी पूरी तरह हल नहीं हुए हैं। भाजपा के पास लगातार दो विधानसभा चुनाव जीतने और बड़े नीतिगत फैसलों का दावा है, तो कांग्रेस के पास अपने शासनकाल के औद्योगिक विस्तार और कल्याणकारी प्रयासों का पक्ष रखने का अवसर है। लेकिन किसी भी दल को केवल अपने दावों के आधार पर सफलता का प्रमाणपत्र नहीं मिल सकता।

सू- दोकू क्र.069								
	2			6			1	
3			4			2		
							6	
6				4				
	9		5			6		1
4		3			9			2
	8		2				7	
1		2		4		9		6
नियम		सू-दोकू क्र.68 का हल						
1. कुल 81 वर्ग है,जिसमें 9वर्गों का एक खंड बनता है।		8	7	6	9	5	1	2
2. हर खाली वर्ग में 1से 9 के बीच का कोई एक अंक र सकते है।		1	3	9	2	8	4	5
3. बाएं से दाएं और उपर से नीचे के प्रत्येक कालम,कतार और खंड में 1से9अंक में से किसी भी अंक का इस्तेमाल एक बार ही कर सकते है।		4	5	2	3	7	6	9
		2	8	5	4	6	7	1
		3	1	7	8	9	2	4
		6	9	4	1	3	5	7
		9	4	1	6	2	8	3
		7	2	8	5	1	3	6
		5	6	3	7	4	9	8

बकायेदारों से शत-प्रतिशत वसूली के लिए निर्देश

चमोली(आरएनएस)। उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (यूपीसीएल) के प्रबंध निदेशक (एमडी) पीसी ध्यानी ने विद्युत वितरण मंडल कर्णप्रयाग के सभी विद्युत वितरण खंडों के साथ समीक्षा बैठक की।

बैठक में अभियंताओं एवं सभी कार्मिकों को उत्तराखंड के सभी उपभोक्ताओं की तय समय पर शिकायतों का समाधान करने और बकायेदार उपभोक्ताओं से शत-प्रतिशत राजस्व वसूली सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

एमडी ने शत-प्रतिशत मीटर रीडिंग पर उपभोक्ताओं के बिल जारी करने, खराब मीटरों को प्राथमिकता पर बदले जाने तथा तत्काल बिल संशोधित करने के निर्देश अधीनस्थ अधिकारियों को दिए। वहीं सीएम हेल्प लाइन की सभी शिकायतों के सकारात्मक विजन के साथ व नियत समय पर समाधान किया जाए।

बैठक में बदरीनाथ धाम एवं केदारनाथ धाम में होने वाले विद्युत कार्यों की समीक्षा भी की गई। बैठक में मुख्य अभियंता एनएस बिष्ट, अधीक्षण अभियंता गौरव शर्मा व अनिल वर्मा, अधिशासी अभियंता राहुल चानना, शैलेंद्र बिष्ट, धर्मवीर सिंह, मनोज कुमार अग्रवाल, अनुभाग अधिकारी चंद्र सिंह बुटोला आदि मौजूद रहे।

फिर साथ आए श्रेयस और सुभाष घई, फिल्म मान्या का पोस्टर रिलीज

संवाददाता
मुंबई। सुभाष घई एक बार फिर अपनी नई फिल्म मान्या के जरिए दर्शकों के सामने एक संवेदनशील कहानी पेश करने जा रहे हैं। फिल्म में श्रेयस तलपड़े मुख्य भूमिका में नजर आएंगे।
खास बात यह है कि दोनों करीब दो दशक बाद साथ काम कर रहे हैं। फिल्म का नया पोस्टर भी रिलीज हो चुका है। 24 अक्टूबर को मुक्ता

आर्ट्स ने अपने 48 साल पूरे किए। इसी मौके पर मान्या का नया पोस्टर सामने आया। इस साल सुभाष घई भारतीय सिनेमा में अपने 5० साल पूरे कर रहे हैं। ऐसे में यह फिल्म उनके लंबे फिल्मी सफर का एक खास पड़ाव मानी जा रही है।

सुभाष घई ने अपने करियर में कालीचरण, कर्ज, हीरो, परदेस और ताल जैसी पॉपुलर फिल्में दी हैं। वहीं इकबाल, ब्लैक एंड व्हाइट और जॉर्जस पार्क जैसी फिल्मों के जरिए उन्होंने सामाजिक मुद्दों और संवेदनशील कहानियों को भी पर्दे पर उतारा है। मुक्ता आर्ट्स अब फिल्मों के साथ एनिमेशन, ओटीटी सीरीज और डॉक्यूमेंट्री जैसे क्षेत्रों में भी अपने काम का विस्तार

कर रहा है।
मान्या एक किशोर लड़के की जिंदगी पर केंद्रित है। फिल्म केवल उसके अपराध पर ध्यान देने के बजाय उसके पीछे की परिस्थितियों और इंसानी पहलुओं को



समझने की कोशिश करेगी। फिल्म का निर्देशन समीर जोशी ने किया है। इसका निर्माण मुक्ता आर्ट्स, पुनीत अग्रवाल और राहुल पुरी ने स्लो बर्न एंटरटेनमेंट के सहयोग से किया है। फिल्म में श्रेयस तलपड़े के साथ संवेदना सुवालका, दिव्या शर्मा, प्रियदर्शिनी पूजा और जोहेब फारूकी भी अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे। संवेदना सुवालका को फिल्म दृश्यम 2 में भी देखा गया है। मान्या को लेकर सुभाष घई ने कहा कि मुक्ता आर्ट्स के लिए यह एक महत्वपूर्ण शुरुआत है और कंपनी आगे भी ऐसी कहानियां लेकर आएगी, जो दर्शकों से जुड़ सकें। उन्होंने करीब दो दशक बाद श्रेयस तलपड़े के साथ काम करने पर खुशी जताई।



घने देवदार जंगलों के बीच भगवान जगन्नाथ जी

मैंने अपने जीवनकाल में इतने सघन और विशुद्ध देवदार के जंगलों के बीच स्थित ऐसा मंदिर नहीं देखा। समय मिले तो इसके दीदार अवश्य करें। चलो आज बात करते हैं भगवान जगन्नाथ जी के बारे में और आपको सीधे लिए चलते हैं भगवान जगन्नाथ जी के मंदिर निसमौर गाँव में। भगवान जगन्नाथ को हिन्दू धर्म में भगवान विष्णु के पूर्ण अवतार श्रीकृष्ण का ही स्वरूप माना जाता है। उन्हें जगत के नाथ (ब्रह्मांड के स्वामी) के रूप में पूजा जाता है।

श्रीकृष्ण का रूप: धार्मिक ग्रंथों और परंपराओं के अनुसार, भगवान जगन्नाथ स्वयं भगवान श्रीकृष्ण हैं।

पूर्णावतार और परब्रह्म: कई संप्रदायों में उन्हें केवल अवतार न मानकर स्वयं शपरब्रह्म (समस्त अवतारों के स्रोत या अवतारी) माना गया है।

परिवार: पुरी मंदिर में उनके साथ उनके बड़े भाई बलभद्र (बलराम) और बहन सुभद्रा भी विराजमान होते हैं। इधर उत्तरकाशी जिले में भगवान जगन्नाथ जी का मुख्य और सबसे प्रसिद्ध प्राचीन मंदिर साल्ड गांव में स्थित है। इसके अलावा वरुणा घाटी के अन्य तीन गांवों में भी इनके मंदिर हैं। जिनमें बड़ेशी, कवां और निसमौर।

साल्ड गांव का जगन्नाथ मंदिर: यह प्राचीन मंदिर उत्तरकाशी शहर से लगभग 6 से 7 किलोमीटर की दूरी पर, वरुणा नदी के तट पर और देवदार के घने जंगलों के बीच स्थित है। इस मंदिर का निर्माण 12वीं शताब्दी (कत्यूरी राजवंश के समय) का माना जाता है। कुछ मान्यताओं के अनुसार इसका जीर्णोद्धार आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा भी कराया गया था। यहाँ भगवान जगन्नाथ को वरुणा घाटी के करीब 10 से 12 गांवों के आराध्य (ग्राम देवता) के रूप में पूजा जाता है। ओडिशा के पुरी की तरह यहाँ भी हर साल आषाढ़ मास में पारंपरिक और पहाड़ी अंदाज में भव्य रथ यात्रा निकाली जाती है। उत्तरकाशी में हर साल आयोजित होने वाली प्रसिद्ध पंचकोसी यात्रा भी इसी मंदिर से होकर गुजरती है।

◆लोकेंद्र सिंह बिष्ट

गंगोत्री विधानसभा से बीजेपी दावेदार

29 को महिला कार्मिकों के लिए सार्वजनिक अवकाश घोषित

संवाददाता

देहरादून। उत्तराखण्ड शासन ने 29 अक्टूबर को महिला कार्मिकों के लिए सार्वजनिक अवकाश घोषित कर दिया है। आज यहां सचिव राजेन्द्र कुमार के द्वारा अधिसूचना जारी करते हुए बताया कि उत्तराखण्ड राज्य के अधीन शासकीय/ अशासकीय कार्यालयों/शैक्षणिक संस्थानों, शासकीय प्रतिष्ठानों में कार्यरत महिला कार्मिकों को प्रदेश भर में करवा चौथ पर्व हेतु 29 अक्टूबर बृहस्पतिवार को सार्वजनिक अवकाश घोषित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान की गयी है।



जिला स्तरीय परिवाद समिति की बैठक सम्पन्न

हमारे संवाददाता

हरिद्वार। जिला स्तरीय परिवाद समिति (पॉश एक्ट) की एक आवश्यक बैठक जिला प्रोबेशन अधिकारी अविनाश भदौरिया के कार्यालय में सम्पन्न हुई।

बैठक में कुछ पुराने मामले जिन पर उत्तराखंड शासन ने जिलाधिकारी हरिद्वार मयूर दीक्षित के माध्यम से स्थानीय परिवाद समिति (पॉश एक्ट) को शिकायतकर्ता द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों की जांच के लिए आदेश दिये हैं, इस मामले पर समिति ने विस्तृत चर्चा की तथा समिति ने साक्ष्यों को जांच के लिए अग्रसारित करने के आदेश दिए। बैठक की अध्यक्षता डाक्टर मनु शिवपुरी ने की बैठक में सचिव समिति जिला प्रोबेशन अधिकारी अविनाश भदौरिया, श्रीमती सुमन कुटियाल, वरिष्ठ पत्रकार श्रीमती शशि शर्मा, एडवोकेट रश्मि उपाध्याय तथा विनिता मेहता उपस्थित रहे। बैठक में जन जागरूकता के उद्देश्य से सार्वजनिक स्थानों पर बैनर होर्डिंग लगाने और विभिन्न विभागों में इंटरनल कमेटियां गठित करने के मसले पर नई अपडेट ली गई।

गोरखा दशै-दीपावली महोत्सव एवं राजकीय मेला में भारतीय एवं नेपाली सांस्कृतिक कार्यक्रम की रहेगी धूम

संवाददाता

देहरादून। गोरखा दशै-दीपावली महोत्सव राजकीय मेला में भारतीय व नेपाली सांस्कृतिक कार्यक्रम की धूम रहेगी।

आज यहां परेड ग्राउंड स्थित एक क्लब में वीर गोरखा कल्याण समिति के अध्यक्ष कमल थापा एवं अन्य सदस्यों ने संयुक्त रूप से पत्रकार को यह जानकारी देते हुए बताया कि गोरखा दशै-दीपावली महोत्सव एवं राजकीय मेला 2026 का भव्य शुभारंभ प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी वीर गोरखा कल्याण समिति द्वारा आयोजित किया जा रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के अलावा नेपाल के कार्यवाहक राजदूत डॉ.सुरेन्द्र थापा मुख्य रुप से पहुंच रहे हैं। खास बात यह है कि इस कार्यक्रम में जहां सांस्कृतिक कार्यक्रमों की राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर धूम रहेगी, वहीं कार्यक्रम में मयूर नृत्य के भी प्रस्तुतियां होंगी वहीं आकाश थापा की भी मनमोहक कार्यक्रम आकर्षण के केंद्र होंगे। वहीं नेपाली सेल रोटी, गोरखाली चटनी, फिनी, चुकानी, गुंडरूक के साथ साथ उत्तराखंड के पारंपरिक व्यंजन का लुफ्त लोग उठा सकते हैं। उन्होंने बताया कि समिति इस बार दसवीं बार गोरखा दशै दिवाली मेले का आयोजन कर रही है। गढ़ी कैंट स्थित महिंद्रा ग्राउंड में आयोजित होने जा रहे इस तीन दिवसीय कार्यक्रम में



मुख्य रूप से प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज, गणेश जोशी, प्रदीप बत्रा, नेपाल के कार्यवाहक राजदूत डॉ.सुरेन्द्र थापा, विधायक विनोद चमोली, महापौर सौरभ थपलियाल शिरकत कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि वीर गोरखा कल्याण समिति का मुख्य उद्देश्य जहां आपसी सद्भाव पैदा करना है वहीं गोरखा समुदाय की पारंपरिक संस्कृति को बेहतर बनाना एवं बरकरार रखना है। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि गोरखा दशै-दीपावली महोत्सव एवं राजकीय मेला 2026 के इस भव्य व बेहतरीन आकर्षक कार्यक्रम में बहुत सारे स्टॉल भी लगाए जा रहे हैं, जहां उत्तराखंड एवं नेपाल के पारंपरिक वेशभूषा खान-पान से लोग रूबरू होंगे। साथ ही इस बार के कार्यक्रम में गढ़वाली, कुमाऊनी, जौनसारी सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ-साथ नेपाल के प्रसिद्ध लोकनृत्य, संगीत की शानदार

प्रस्तुतियां होंगी। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर के कई कलाकारों की प्रस्तुति इस भव्य कार्यक्रम में रहेगी और यह सभी आकर्षण का केंद्र रहेंगे। इस राजकीय मेले में पद्मश्री सम्मान से अलंकृत कुछ अतिथियों को भी निमंत्रण दिया गया है एवं उन्होंने समिति अपने विशेष सम्मान से सम्मानित करेंगे। पत्रकार वार्ता में समिति के संरक्षक ई. मेग बहादुर थापा, मेजर बी पी थापा, मेजर अमर राई, अध्यक्ष कमल थापा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष उर्मिला तमांग, उपाध्यक्ष सूर्य बिक्रम शाही, महासचिव विशाल थापा, कोषाध्यक्ष/मीडिया प्रभारी टेकु थापा, सचिव देविन शाही, सह-सचिव आशु थापा, सांस्कृतिक सचिव देव कला दिवान सह सांस्कृतिक सचिव करमिता थापा, संगठन मंत्री लोकेश बन, सोनु गुरूगं, सदस्य पूरन बहादुर थापा, यामु राना, शाहिल राणा, सोना शाही, ज्योति राना, बबिता गुरुंग, एनबी थापा, बुद्धेश राई, मीन गुरुंग मौजूद रहे।

‘एक नवंबर को दिल्ली में वोट बचाओ, देश बचाओ रैली में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल होंगे’

संवाददाता

देहरादून। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अजय कुमार ने कहा कि एक नवंबर को दिल्ली में वोट बचाओ, देश बचाओ रैली निकाली जाएगी। इसमें उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश से बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल होंगे। उन्होंने मतदाता सूची से नाम काटे जाने का आरोप लगाते हुए अलग-अलग राज्यों के आंकड़े भी बताए।

अजय कुमार के अनुसार, उत्तर प्रदेश में 13 करोड़ 14 लाख, मध्य प्रदेश में 34 लाख, ओडिशा में 20 लाख और उत्तराखंड में 8.02 लाख वोट एसआईआर के तहत काट दिए गए हैं। उन्होंने इन आंकड़ों के आधार पर मतदाता सूची से नाम हटाए जाने का मुद्दा उठाया।

कांग्रेस की ओर से प्रस्तावित रैली में मतदाता सूची से जुड़े इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया जाएगा। अजय कुमार ने उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ताओं से रैली में शामिल होने की बात कही।



शराब के साथ महिला सहित चार गिरफ्तार दो वाहन सीज

संवाददाता

टिहरी। पुलिस ने शराब के साथ महिला सहित चार लोगों को गिरफ्तार कर दो वाहन सीज कर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है।

मिली जानकारी के अनुसार वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्रीमती श्वेता चौबे के निर्देशन में जनपद में अवैध शराब की तस्करी, बिक्री एवं परिवहन पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए संचालित ऑपरेशन प्रहार के तहत टिहरी पुलिस द्वारा लगातार सघन चेकिंग एवं कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में पिछले 24 घंटों के दौरान चार अलग-अलग मामलों में चार अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। कार्रवाई के दौरान कुल 46 पेटी अंग्रेजी शराब, 10 पेटी प्रीमियम स्ट्रॉंग बीयर एवं 80 टेट्रा पाउच अवैध देशी शराब बरामद

की गई। शराब तस्करी में प्रयुक्त एक पिकअप एवं एक अल्टो कार को भी जब्त किया गया। थाना घनसाली पुलिस चौकी चमियाला में वाहन चेकिंग के दौरान पिकअप से 32 पेटी सोलमेट ब्लू क्वार्टर, 06 पेटी सोलमेट ब्लू हाफ एवं 10 पेटी प्रीमियम स्ट्रॉंग बीयर बरामद की गई। मौके से वाहन चालक रविंद्र बिष्ट पुत्र बलबीर सिंह बिष्ट निवासी कस्बा डुंडा, जनपद उत्तरकाशी को गिरफ्तार कर पिकअप जब्त की गई। इस संबंध में आबकारी अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया।थाना देवप्रयाग: चौकी बछेलीखाल क्षेत्र में चेकिंग के दौरान अल्टो कार से चंडीगढ़ मार्का अंग्रेजी शराब की 06 पेटियां (288 पब्बे) बरामद कर जोत सिंह बिष्ट पुत्र रंजीत सिंह बिष्ट

निवासी ग्राम गुराई, थाना हिंडोलाखाल जनपद टिहरी गढ़वाल को गिरफ्तार किया गया। वाहन जब्त कर आबकारी अधि नियम के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया। कोतवाली चंबा: पुलिस ने चेकिंग के दौरान सुरेश पुत्र देवदास निवासी ग्राम सेमल्टा, चंबा जनपद टिहरी गढ़वाल को 02 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब के साथ गिरफ्तार किया। इस संबंध में आबकारी अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया। थाना मुनि की रेती: ढालवाला क्षेत्र के शांति नगर में कार्रवाई के दौरान सकुंती देवी पत्नी किशन साहनी निवासी मायाकुंड, ऋषिकेश जनपद देहरादून को 80 टेट्रा पाउच माल्टा अवैध देशी शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। इस संबंध में आबकारी अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया।

मुख्यमंत्री ने गैरसैण में 231.91 करोड़ की 12 विकास योजनाओं का किया लोकार्पण



संवाददाता

गैरसैण। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गैरसैण (भराड़ीसैण) में जनपद चमोली की 231.91 करोड़ रुपये की 12 विकास योजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। इनमें 197.87 करोड़ रुपये की लागत की 6 योजनाओं का शिलान्यास तथा 34.04 करोड़ रुपये की लागत की 6 योजनाओं का लोकार्पण शामिल है। ये योजनाएं पेयजल, सड़क संपर्क, शिक्षा, स्वास्थ्य, भू-धंसाव से सुरक्षा तथा पुलिस अवस्थापना सुविधाओं से संबंधित हैं। मुख्यमंत्री ने जिन छह योजनाओं का शिलान्यास किया, उनमें सबसे प्रमुख 122.69 करोड़ रुपये की लागत से गैरसैण शहर एवं आसपास की आबादी को पेयजल आपूर्ति के लिए रामगंगा नदी पर

बांध निर्माण की योजना शामिल है। इसके अतिरिक्त 50 करोड़ 18 लाख 68 हजार रुपये की लागत से कर्णप्रयाग विकासखंड के बहुगुणानगर में भू-धंसाव से सुरक्षा संबंधी कार्यों का शिलान्यास किया गया। मुख्यमंत्री ने 12 करोड़ 16 लाख 64 हजार रुपये की लागत से राजकीय पॉलिटेक्निक गैरसैण के भवन निर्माण तथा 22 लाख 75 हजार रुपये की लागत से राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय बहुवाबाण में भवन अनुरक्षण कार्य का भी शिलान्यास किया। इसके साथ ही 6 करोड़ 99 लाख 20 हजार रुपये की लागत से कुमोली रैवान मोटर मार्ग के किलोमीटर 2 से फरखण्डे मोटर मार्ग तथा 5 करोड़ 60 लाख 50 हजार रुपये की लागत से गैरसैण-पञ्जाणा मोटर

मार्ग के किलोमीटर 2 से कुमोली रैवान मोटर मार्ग से संबंधित कार्यों का शिलान्यास किया गया। मुख्यमंत्री ने 34.04 करोड़ रुपये की लागत से पूर्ण हुई छह विकास योजनाओं का लोकार्पण भी किया। इनमें 14 करोड़ 82 लाख 32 हजार रुपये की लागत से खजुरखाल-भण्डारीखोड़-कुनीगाड़ मोटर मार्ग (बहुवाबाण-चौखुटिया) का उच्चीकरण कार्य शामिल है। इसके अतिरिक्त 4 करोड़ 37 लाख 86 हजार रुपये की लागत से राजकीय इंटर कॉलेज गैरसैण में निर्मित ऑडिटोरियम भवन का लोकार्पण किया गया। मुख्यमंत्री ने 4 करोड़ 3 लाख 41 हजार रुपये की लागत से सारकोट-भराड़ीसैण मोटर मार्ग के किलोमीटर 6 से 11 तक सुधार एवं डामरीकरण कार्य तथा 2 करोड़ 17 लाख 98 हजार रुपये की लागत से कारगिल शहीद रणजीत सिंह (आगर-जिनगोड़) मोटर मार्ग के किलोमीटर 1 से 8 तक सुधार, डामरीकरण एवं नवीनीकरण कार्य का भी लोकार्पण किया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने गैरसैण में पुलिस एवं अग्निशमन सुविधाओं को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से निर्मित दो महत्वपूर्ण भवनों का लोकार्पण किया।

गैरसैण में कांग्रेस का हंगामा

काले झंडे लेकर वेल में पहुंचे विधायक

हमारे संवाददाता

गैरसैण। उत्तराखंड विधानसभा के भराड़ीसैण स्थित सदन में सत्र के दूसरे और अंतिम दिन की कार्यवाही शुरू होते ही जमकर हंगामा हुआ। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या से जुड़े कथित भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर कांग्रेस विधायकों ने काले झंडे लहराए और सदन के वेल में पहुंचकर विरोध जताया। विपक्ष के हंगामे के बीच विधानसभा अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक स्थगित कर दी।

सत्र के अंतिम दिन वित्तीय वर्ष 2026-27 के अनुपूर्क बजट पर चर्चा और मतदान होना है। इसके साथ ही विभिन्न विधेयकों पर भी विचार किया जाना है। हालांकि, सदन की शुरुआत से ही सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बयानबाजी देखने को मिली। विपक्ष जहां कथित भ्रष्टाचार के आरोपों और अन्य जनहित के मुद्दों पर चर्चा की मांग कर रहा है, वहीं सत्ता पक्ष की ओर से भी कांग्रेस को घेरने की कोशिश की गई।

कांग्रेस नेता प्रीतम सिंह ने कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या से जुड़े कथित भ्रष्टाचार के आरोपों को सदन में उठाते हुए मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की। वहीं, रेखा आर्या ने कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार करते हुए वर्ष 2012 से 2017 के दौरान रही कांग्रेस सरकार के कार्यकाल का जिक्र किया। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या ने सदन में महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा कराने की बात कही। दूसरी ओर, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विपक्ष की ओर से काम रोको प्रस्ताव लाने की मंशा पर सवाल उठाए। इन बयानों के बीच सदन में राजनीतिक टकराव की स्थिति बनी रही। विधानसभा की कार्यवाही शुरू होते ही कांग्रेस विधायक काले झंडे लेकर सदन के वेल में पहुंच गए और विरोध प्रदर्शन किया। हंगामे के चलते कार्यवाही सुचारू रूप से नहीं चल सकी। इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ने सदन को दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया। उधर, सत्ता पक्ष के विधायकों ने चकराता में एक परिवार को कांग्रेस नेताओं की ओर से कथित तौर पर धमकी दिए जाने का मामला उठाया। उन्होंने इस प्रकरण की जांच कराने और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। इस तरह सत्र के दूसरे दिन भी सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर जारी रहा।

ट्रेन की चपेट में आने से हाथी की मौत

हमारे संवाददाता

नैनीताल। लालकुआं से रूद्रपुर जा रही बाघ एक्सप्रेस ट्रेन की चपेट में आकर एक नर हाथी की छतरपुर हल्दी रेलवे ट्रैक के बीच मौत हो गई।

बताया जाता है कि तराई केन्द्रीय वन प्रभाग रूद्रपुर डिवीजन की टांडा रेज की घटना है। घटना से नर हाथी का दांत टूट गया है। जिसके बाद टूटे दांत को रेलवे ने अपने कब्जे में ले लिया है। रेलवे वन विभाग को बुधवार को दांत सौंप देगा। स्टेशन ट्रैक के पिलर संख्या 55/8 के पास की घटना बताई गई है। इस घटना के बाद वन विभाग में अफरा तफरी का माहौल है। वन क्षेत्राधिकारी रूपनारायण गौतम सहित कई वन कर्मचारियों मौके पर पहुँचे। इस नर हाथी को मौत की जिम्मेदारी किसकी होगी! क्या यूँ ही वन विभाग की गलतियों से हाथियों की मौत होती रहेगी ? इसके लिये वन क्षेत्राधिकारी क्या जिम्मेदार होंगे ? ये पहली घटना नहीं है, इससे पूर्व भी यहां कई हाथी अपनी जान गंवा चुके हैं लेकिन आज तक किसी को इसके लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया गया।



पुलिस की पहल, एकल वरिष्ठ नागरिकों से मिलकर जानी कुशलक्षेम

हमारे संवाददाता

टिहरी। वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा, सम्मान एवं कुशलक्षेम सुनिश्चित करने के उद्देश्य से वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, टिहरी गढ़वाल श्रीमती श्वेता चौबे के निर्देशन में टिहरी पुलिस द्वारा जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों में रह रहे वरिष्ठ एवं एकल वरिष्ठ नागरिकों से संपर्क कर उनकी कुशलक्षेम जानी गई। इस अभियान के अंतर्गत कैम्पटी, देवप्रयाग, कीर्तिनगर एवं थल्यूड पुलिस द्वारा अपने-अपने क्षेत्र में निवासरत वरिष्ठ नागरिकों से व्यक्तिगत रूप से मुलाकात कर एवं फोन के माध्यम से वार्ता की गई। पुलिस कर्मियों ने बुजुर्गों के स्वास्थ्य, दैनिक जीवन में आने वाली समस्याओं तथा उनकी सुरक्षा से संबंधित आवश्यक जानकारी प्राप्त की और उनकी समस्याओं एवं सुझावों को संवेदनशीलता के साथ सुना।

कैम्पटी क्षेत्र में पुलिस टीम द्वारा ऐसे वरिष्ठ नागरिकों से विशेष रूप से मुलाकात की गई, जिनकी देखभाल के लिए परिवार का कोई सदस्य उपलब्ध नहीं है। जरूरतमंद बुजुर्गों को आवश्यकतानुसार खाद्य सामग्री वितरित कर उन्हें हरसंभव सहायता उपलब्ध कराने का भरोसा दिलाया गया। पुलिस ने बुजुर्गों की समस्याओं एवं सुझावों को गंभीरता से सुना और उन्हें आश्वस्त किया कि उनकी सुरक्षा एवं सहायता के लिए टिहरी पुलिस सदैव तत्पर है। पुलिस द्वारा वरिष्ठ एवं एकल वरिष्ठ नागरिकों को वर्तमान समय में बढ़ रहे साइबर अपराधों के प्रति जागरूक किया गया। उन्हें अनजान फोन कॉल, संदिग्ध लिंक, फर्जी कॉल तथा साइबर ठगी के विभिन्न तरीकों से सतर्क रहने

की जानकारी दी गई। साथ ही, किसी भी अनजान व्यक्ति के साथ बैंक खाते से संबंधित जानकारी, ओटीपी अथवा अन्य गोपनीय जानकारी साझा न करने की अपील की गई। साइबर ठगी का शिकार होने पर तत्काल साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर शिकायत दर्ज कराने के संबंध में भी जानकारी दी गई। पुलिस द्वारा ग्राम प्रधानों एवं ग्राम प्रहरियों को अकेले रहने वाले वरिष्ठ नागरिकों की नियमित कुशलक्षेम लेने तथा उनकी सुरक्षा के प्रति विशेष सतर्कता बरतने के लिए निर्देशित किया गया। वरिष्ठ नागरिकों को थानों के मोबाइल नंबर एवं संबंधित हल्का/बीट प्रभारियों के मोबाइल नंबर भी उपलब्ध कराए गए, ताकि आवश्यकता पड़ने पर वे तत्काल पुलिस से संपर्क कर सकें।

अंकिता केस में 'वीआईपी' का रहस्य: सीबीआई मुख्यालय में पांच घंटे आशुतोष नेगी से पूछताछ

कार्यालय संवाददाता

नई दिल्ली/देहरादून। अंकिता भंडारी हत्याकांड में कथित वीआईपी की पहचान का सवाल फिर सुर्खियों में है। उत्तराखंड क्रांति दल डेमोक्रेटिक के केंद्रीय कार्यकारी अध्यक्ष आशुतोष नेगी ने दिल्ली स्थित केंद्रीय जांच ब्यूरो मुख्यालय में करीब पांच घंटे तक चली पूछताछ के दौरान अपने बयान दर्ज कराए। अंकिता प्रकरण में कथित वीआईपी का नाम स्पष्ट करने की मांग के बीच इस घटनाक्रम ने एक बार फिर जांच के उन सवालों को चर्चा के केंद्र में ला दिया है, जिनके जवाब का इंतजार प्रदेश को है।

अंकिता भंडारी हत्याकांड में कानूनी कार्रवाई के बावजूद कथित वीआईपी की



◆कथित वीआईपी का नाम उजागर करने की मांग फिर तेज
◆तीन दोषियों को सजा, फिर भी कथित वीआईपी पर सवाल

पहचान को लेकर सार्वजनिक बहस थमी नहीं है। आखिर वह कौन था, जिसकी चर्चा इस मामले में लगातार होती रही? क्या जांच में सामने आए सभी तथ्यों का पूरी तरह

खुलासा हुआ है? और क्या उन सवालों के जवाब मिल पाएंगे, जिन्हें लेकर अंकिता को न्याय दिलाने की मांग उठती रही है? आशुतोष नेगी लंबे समय से इस प्रकरण में कथित वीआईपी का नाम स्पष्ट करने की मांग करते रहे हैं। दिल्ली में सीबीआई मुख्यालय में पांच घंटे तक पूछताछ और बयान दर्ज होने के बाद अब निगाहें जांच एजेंसी की अगली कार्रवाई पर हैं। हालांकि, पूछताछ के दौरान नेगी ने कौन-से तथ्य या साक्ष्य प्रस्तुत किए और सीबीआई ने उनसे किन बिंदुओं पर सवाल किए, इसकी विस्तृत आधिकारिक जानकारी सामने आना बाकी है।

अंकिता हत्याकांड उत्तराखंड की संवेदनाओं से जुड़ा मामला है। ऐसे में कथित

वीआईपी की पहचान को लेकर उठते सवालों का जवाब केवल अटकलों से नहीं, बल्कि जांच के प्रमाणित तथ्यों और आधिकारिक निष्कर्षों से मिलना चाहिए। किसी व्यक्ति का नाम बिना प्रमाण सामने रखना न्याय और जांच दोनों के लिहाज से उचित नहीं होगा।

अब सवाल सीधा है कि क्या सीबीआई की जांच कथित वीआईपी को लेकर बने संशय पर निर्णायक स्थिति स्पष्ट करेगी? पांच घंटे की पूछताछ के बाद आशुतोष नेगी के बयान जांच का हिस्सा बन चुके हैं। अब देखना होगा कि इन बयानों से जांच को क्या दिशा मिलती है और अंकिता प्रकरण के अनुत्तरित सवालों पर कब तक स्थिति साफ होती है।

आर.एन.आई.- 59626/94

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक श्रीमती पुष्पा कांति कुमार द्वारा दिग्विजय सिनेमा बिल्डिंग घंटाघर, देहरादून से प्रकाशित तथा अवि प्रिंटेर्स 21 ईसी रोड, देहरादून से मुद्रित।

प्रधान संपादक

कांति कुमार

संपादक

पुष्पा कांति कुमार

समाचार संपादक

आनंद कांति कुमार

कानूनी सलाहकार:

वी के अरोड़ा, एडवोकेट

बैजनाथ, एडवोकेट

कार्यालय: दिग्विजय सिनेमा बिल्डिंग देहरादून।

मो. 9358134808

नोट: सभी विवादों के लिये देहरादून न्यायालय ही मान्य होगा, प्रकाशित सामग्रियों के लिए प्रिंटेर्स की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।